vishikhamedia@gmail.com
विभिन्न विषयों पर आधारित राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका
RNI No. UTTHIN/2021/80704

_vishikhamedia/ vishikhamedia/

तीर निशाने पर

विशिखा

मूल्य:35 रूपये
vishikhamedia vishikhamedia.in
वर्ष:05 अंक:2 फरवरी 2025 पृष्ठ:32

उत्तराखण्ड संस्करण

उत्तराखंड की देवभूमि के साथ खेलभूमि के तौर पर भी बनी पहचान- केंद्रीय गृह मंत्री

राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से उत्तराखंड में नई संभावनाओं और उम्मीदों की शुरुआत सीएम धामी

विशिखा

न्यूज़ 24x7

आपकी बात, आपके साथ

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

अब डिजिटल एडिशन में भी उपलब्ध

www.vishikhamedia.in

अंदर

महाकुंभ से निखरा हिन्दुत्व और बढ़ा योगी का सियासी कद 08

11 यूपीआई पेमेंट करने का तरीका बदला, अब ट्रांजेक्शन आईडी केवल अल्फान्यूमेरिक

12 क्या दलितों का मोहभंग हो रहा है भाजपा से

14 क्या पलायन के असली जिम्मेदार जगमोहन थे?

16 दलितों को लुभाने के लिए कांग्रेस का नया अभियानः जय बापू, जय भीम

18 अब थाईलैंड में भी समलैंगिक विवाह को मिली मान्यता, हाईप्रोफाइल गे कपल ने की शादी

19 सर्च रिपोर्ट के बगैर लोन मंजूर ना करें बैंक-सुप्रीम कोर्ट

20 मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू

22 दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए कांग्रेस की सियासी चालें तेज

24 इसरो की १००वीं सफलताः एनवीएस-०२ के जरिये भारत का अपना नैविगेशन सिस्टम नाविक हुआ और मजबूत

25 कनाडा की नई सरकार भारत से बनायेगी अच्छे संबंध

26 हिन्दुओं को इग्नोर करने वाले नेताओं को बदलनी

विशिखा
तीर निशाने पर
अंक: 2 वर्ष:05, फरवरी 2025

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
प्रियल श्रीवास्तव
सम्पादक
अनिल कुमार श्रीवास्तव
डिजाइन
देवेन्द्र नेगी, उत्तराखण्ड

विशिखा
तीन निशाने पर

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक एवं संपादक **अनिल कुमार श्रीवास्तव** द्वारा **भास्कर प्रिंटिंग प्रेस, डी.बी. कॉर्प लिमिटेड** शिवदासपुरा, टोंक रोड़, जयपुर से छपवाकर एवं **विशिखा मीडिया** सी-29, शिवलोक कॉलोनी, लाडपुर-राजपुर रोड़, देहरादून 248008 उत्तराखण्ड से प्रकाशित

पाठकों से अनुरोध है कि पत्रिका मे प्रकाशित सामग्री के विषय मे अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझाव अवश्य भेजें। अपनी प्रतिक्रियाएं एवं सुझावों को आप हमें vishikhamedia@gmail.com पर ई-मेल भी कर सकते हैं।
लेखकों से निवेदन है कि कृपया अपनी स्व-लिखित एवं मौलिक रचनायें ही भेजें। रचनाओं के साथ अपना पूरा नाम, पता, मोबाइल नंबर, ई-मेल एवं फोटो अवश्य भेजें। रचनाओं के छापने या न छापने का अधिकार संपादकीय मंडल का होगा। अस्वीकृत रचनायें लौटाई नहीं जाएंगी।
पत्रिका मे प्रकाशित सभी लेख एवं रचनाओं में संपादक की सहमति हो, यह आवश्यक नहीं है। पत्रिका मे प्रकाशित आलेख एवं रचनायें लेखकों के निजी विचार हैं। प्रकाशित सामग्री के उपयोग करने से पूर्व में संपादक की लिखित सहमति आवश्यक है।
*किसी भी तरह के विवादों का न्याय क्षेत्र जयपुर (राजस्थान) होगा।
*पत्रिका मे प्रकाशित कुछ चित्र, लेख एवं आंकड़ो को इन्टरनेट एवं अन्य वेवसाइट से लिया गया है।

विशिखा न्यूज़ 24x7
आपकी बात. आपके साथ

सम्पादक की कलम से

अनिल कुमार श्रीवास्तव

प्रयागराज में मकर संक्रांति से आरंभ होने वाला महाकुंभ दिन प्रतिदिन एक नया इतिहास बना रहा है। पूरे महाकुंभ के दौरान सरकार को करीब 30 से 35 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन इस उम्मीद से परे प्रयागराज में प्रतिदिन क□क□रीब 60 से 70 लाख लोग स्नान करने आ रहे हैं, महास्नान पर तो ये आंकड़ा एक करोड़ से भी ऊपर पहुंच जाता है।

प्रयागराज के इस महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच गई थी. यह भगदड़ देर रात करीब 1.30 बजे संगम नोज इलाके में हुई थी. इस भगदड़ में आधिकारिक तौर पर क□क□रीबन 30 लोगों की मौत हो गई थी. ऐसा नहीं है कि कुंभ मेले में भगदड़ की घटनाएं पहले नहीं हुई हैं

वर्ष 1954 में मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में भगदड़ मची थी. इसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी.

साल 2013 में भी प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से 42 लोगों की मौत हो गई थी.

साल 2003 में नासिक में भगदड़ मचने से क□क□रीब 39 लोगों की मौत हो गई थी.

लेकिन इस बार के महाकुंभ में भगदड़ की घटना के बाद विपक्ष को सरकार की आलोचना करने का मौका मिल गया.

उम्मीद से अधिक लोगों का महाकुंभ में पहुंचना और सरकार की दूरदर्शिता के परिणाम स्वरूप ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना बन गया, वरना करोड़ों की भीड़ जब बेकाबू हो जाती है तो उसे संभालना मुश्किल हो जाता है। सरकार भी इस मामले में जांच कर रही है कि महाकुंभ में हुआ ये हादसा सिर्फ हादसा ही था, या इसमें कोई साजिश थी।

दूसरी ओर अब सरकार को भी इस घटना से सबक लेते हुए आगामी दिनों में होने वाले महा स्नान पर अपनी रणनीति नए सिरे से बनानी होगी, जिससे भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके।

शेष फिर...

प्रधानमंत्री बनने का मार्ग कैसे प्रशस्त किया था इंदिरा गांधी ने

अजय श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश

ताशकंद में प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री की मौत के ठीक आठ दिन बाद 19 जनवरी, 1966 को प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। इसमें इंदिरा गाँधी को 355 और मोरारजी देसाई को केवल 169 वोट मिले। ताकतवर मोरारजी देसाई को हराना आसान नहीं था मगर इंदिरा गाँधी ने अपनी सूझबूझ से असंभव को संभव बना लिया।

राजनीति में सीमित अनुभव रखनेवाली इंदिरा अल्पभाषी थी तथा लोगों से कम ही घुलमिल पातीं थी। प्रधानमंत्री पद पर इंदिरा गाँधी का चयन कैसे संभव हुआ इसे कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्यप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा ने अपनी किताब ष्ज्भ्म चैृज छम्भ्त्न म्त|रू च्वस्प्ज्प्ब|स- डम्डव्प्त्ै में विस्तार से लिखा है। उन दिनों डी पी मिश्रा को भारतीय राजनीति का चाणक्य कहा जाता था। नेहरू और के. कामराज दोनों के गुडबुक में पंडितजी शामिल थे। वे अपनी किताब में लिखते हैं कि 11 जनवरी 1966 की सुबह साढ़े पांच बजे दिल्ली से इंदिरा गाँधी का फोन आता है और वे उन्हें सूचित करती हैं कि लालबहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई है और आप आज ही दिल्ली आकर उनसे मिलें। चतुर डी पी मिश्रा समझ गए थे कि इंदिरा प्रधानमंत्री बनने की जुगत में हैं।

भारतीय राजनीति के चाणक्य डी पी मिश्रा दिल्ली में इंदिरा गाँधी से मिलते हैं। इंदिरा उनसे अपनी दावेदारी का समर्थन मांगती हैं। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। डी पी मिश्रा ने अपनी किताब में लिखा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा भी पूर्णकालिक प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, और इसी सिलसिले में गुलजारी लाल ने उनसे मुलाकात कर समर्थन मांगा था। मेरे सम्मुख दो लोग थे मगर एक और खिलाडी था जो पर्दे के पीछे था। वो थे कांग्रेस अध्यक्ष के. कामराज। कामराज ने कभी प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश जाहिर नहीं की, मगर उम्मीदवारी का खंड़न भी नहीं किया। वे ताकतवर सिंडिकेट के मुखिया थे और वे जो चाहते कर सकते थे। सिंडिकेट के लोग चाहते थे कि हर हाल में कामराज ही प्रधानमंत्री बने। इधर मोरारजी देसाई ने अपनी उम्मीदवारी के झंडे गाड रखे थे। दरअसल धनवान गुजरात लाबी ने मोरारजी पर अपना दाव लगा रखा था। वैसे भी नेहरू के निधन के बाद मोरारजी भाई ही प्रधानमंत्री पद के स्वभाविक उम्मीदवार थे मगर देसाई की बदजुबानी और अहंकार ने उनसे कनिष्ठ शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया। उन दिनों राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा रहती थी कि मोरारजी देसाई ने दोस्तों से अधिक दुश्मन बनाए हैं।

बताते हैं कि तेरह जनवरी की रात सिंडिकेट नेताओं की गुप्त बैठक हुई। सिंडिकेट के सभी सदस्यों का मत था कि के. कामराज ही प्रधानमंत्री बने और उन्होंने इसके लिए एक प्रस्ताव भी पेश किया। कामराज ने सभी की बातें सुनी और मीटिंग के अंत में प्रधानमंत्री बनने से इंकार कर दिया। बताते हैं कि वो हिंदी नहीं बोल पाते थे और उनका मानना था कि प्रधानमंत्री पद पर आसीन व्यक्ति के लिए हिंदी बोलना अनिवार्य है। कारण और भी रहे होंगे मगर ये बात खुलकर सामने आई थी।

कांग्रेस अध्यक्ष के. कामराज ने 14 जनवरी को प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को तलाशने के लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। इस बैठक में उम्मीदवारों को लेकर कोई निष्कर्ष तो नहीं निकला लेकिन ये फैसला हुआ कि 19 जनवरी को दिवंगत प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री के उत्तराधिकारी की घोषणा होगी। यहाँ से डी पी मिश्रा का खेल शुरू हो गया। उन्होंने सभी कांग्रेस शासित मुख्यमंत्रियों की एक मीटिंग बुलाई। बैठक में सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के लिए सर्वप्रथम कामराज को कहा जाएगा। अगर वो राजी हो गए तो उनके नाम की मुहर लगेगी नहीं तो इंदिरा गाँधी का नाम आगे बढ़ाया जाएगा।

बैठक खत्म होते ही कांग्रेस शासित अधिकांश मुख्यमंत्रियों ने के. कामराज से मिलकर प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने की अपील की। दो राज्य उत्तरप्रदेश और गुजरात के मुख्यमंत्री इसमें शामिल नहीं थे, क्योंकि वे मोरारजी भाई का समर्थन कर रहे थे। समर्थन से गदगद कामराज ने कहा मैं प्रधानमंत्री नहीं बनूँगा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष ही ठीक हूँ। डी पी मिश्रा ने कामराज से आग्रह किया कि वे ये बात प्रेस के सामने बोल दें, जिससे भ्रम की स्थिति न रहे। कामराज ने एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि मैं प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं हूँ। डी पी मिश्रा के आग्रह पर के. कामराज भी इंदिरा गाँधी के नाम पर सहमत हो गए।

कांग्रेस के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने मोरारजी देसाई को ये सलाह दी कि वो इंदिरा के नाम पर अपनी सहमति दे दें, मगर मोरारजी भाई ने साफ इंकार कर दिया। 19 जनवरी को प्रधानमंत्री पद के चुनाव के लिए वोटिंग हुई। जिसमें इंदिरा गाँधी को 355 और मोरारजी देसाई को केवल 169 वोट मिले। इंदिरा गाँधी को जीतना ही था, क्योंकि डी पी मिश्रा ने व्यूहरचना ही ऐसे की थी। 24 जनवरी 1966 को इंदिरा गाँधी ने स्वतंत्र भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

उत्तराखंड की देवभूमि के साथ खेलभूमि के तौर पर भी बनी पहचान- केंद्रीय गृह मंत्री शाह

राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन से उत्तराखंड में नई संभावनाओं और उम्मीदों की शुरुआत सीएम धामी

केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में अन्तरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम गोलापार, हल्द्वानी में 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन समारोह आयोजित किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी. ऊषा ने 38वें राष्ट्रीय खेल के समापन की घोषणा की। इस अवसर पर केन्द्रीय गृह मंत्री ने प्रथम तीन स्थान प्राप्त करने वाले सर्विसेज, महाराष्ट्र और हरियाणा को सम्मानित किया।

केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड के चारों धामों के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री धामी ने उत्तराखंड के हर जिले में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने देवभूमि को राष्ट्रीय खेलों के नक्शे पर 25वें स्थान से 7वें स्थान पर लाने का कार्य किया है।

उत्तराखंड के हर जिले में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखण्ड के चारों धामों के देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड के हर जिले में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री ने देवभूमि को राष्ट्रीय खेलों के नक्शे पर 25वें स्थान से 7वें स्थान पर लाने का कार्य किया है। राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के विजेता खिलाड़ियों ने देवभूमि को खेल भूमि बनाया है। केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी उत्तराखंड के विजेता खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

उत्तराखंड की मेजबानी का देशभर में गुणगान

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड की आयोजन समिति एवं खेल संगठनों की पीठ थपथपाते हुए कहा कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए पूरे देश में उत्तराखंड की तारीफ हो रही है। पूरा देश उत्तराखंड द्वारा की गई शानदार व्यवस्थाओं के गुणगान कर रहा है। भौगोलिक कठिनाइयों के बावजूद उत्तराखंड राज्य ने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में इस कार्य को कुशलतापूर्वक सम्पन्न किया है। उन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेल के सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हार और जीत का खेल से मतलब नहीं है। जीत का जज्बा और हार से निराश न होना, ये खेल का संदेश है। हारने वाले खिलाड़ियों के लिए अगली बार मेडल लाने का मौका है।

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में 38वें राष्ट्रीय खेलों में इको– फ्रेंडली प्रैक्टिसेज एवं इको फ्रेंडली गेम को धरातल में उतारा गया है। खिलाड़ियों के नाम पर पौधारोपण किया गया। राष्ट्रीय खेलों में खिलाड़ियों द्वारा कई नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाए गए हैं, इन रिकॉर्डों से अंतरराष्ट्रीय खेलों में भी भारत के लिए पदक की उम्मीद जगी है। उन्होंने कहा राष्ट्रीय खेलो की यह मशाल उत्तराखंड से अब मेघालय जाएगी। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड

संकल्प से शिखर तक

संगमा ने यह निर्णय लिया है कि नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों में कुछ खेलों के आयोजन से पूरे नॉर्थ ईस्ट को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा को आगामी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी।

हार से लें जीत की प्रेरणा

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में खेलों के वातावरण में सकारात्मक बदलाव आया है। देश भर के कई जिलों में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर, कोचिंग की व्यवस्था, खिलाड़ियो को प्रोत्साहन और पारदर्शी चयन के माध्यम से आज विश्व के खेल पटल पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा भारत के खेलों का भविष्य उज्ज्वल है। खेलों में हर बार नए कीर्तिमान स्थापित हो इसकी व्यवस्था केंद्रीय खेल मंत्री ने की है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री मोदी ने फिट इंडिया और खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाया है। खेल हमें हारने के बाद जितने के लिए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

प्रधानमंत्री को खेल मित्र मानता है हर खिलाड़ी

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सफलता सिर्फ शारीरिक क्षमता से नहीं बल्कि दृढ़ निश्चय और मजबूत मन से प्राप्त होती है। अथक परिश्रम और निरंतर प्रयास खिलाड़ियों को आगे ले जाएगी। इन सभी के माध्यम से खिलाड़ी मेडल तक की यात्रा तय कर सकते हैं। प्रधानमंत्री

नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए। आज हर खिलाड़ी प्रधानमंत्री मोदी को खेल मित्र के रूप में मानता है। उन्होंने कहा 2014 में खेल बजट 800 करोड़ था, जो 2025 दृ 26 में खेल बजट 3800 करोड़ तक पहुंचाया है। अंतरराष्ट्रीय मंचों में भी हमारे खिलाड़ियों ने तिरंगे का मान बढ़ाया है। खिलाड़ियों के मेडल से पता लगता है कि देश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और जीतने की भूख में बढ़ोतरी हुई है।

2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है भारत

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि खेलो इंडिया के माध्यम से उत्तराखंड जैसे छोटे पहाड़ी राज्य ने इतने बड़े खेल आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न किया है। यह बताता है कि भारत का हर राज्य खेलने और खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इस राज्य से, अब फिर राष्ट्रीय खेल का आयोजन एक पहाड़ी राज्यों में जा रहा है। आज खिलाड़ी कई प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारत 2036 में ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार है। 2036 में ओलंपिक के अंदर उत्तराखंड के खिलाड़ी भी मेडल लाकर भारत के तिरंगे का मान बढ़ाएंगे।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री स्व. सुषमा स्वराज एवं पुलवामा में शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि पुलवामा के जवानों की शहादत ने देश को सुरक्षित किया है। जवानों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर करारा जवाब दिया था। इसी के कारण पूरी दुनिया का भारत के प्रति नजरिया बदला है। इससे दुश्मनों को साफ संदेश गया कि भारत की सेना और सीमा से कभी खिलवाड़ नहीं करना है।

महाकुंभ से निखरा हिन्दुत्व और बढ़ा योगी की सियासी कद

प्रयागराज में साधू-संतो का तो जमावाड़ा है ही यहा पहुंचनें वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो श्रद्धालू महाकुंभ पहुंचते हैं वह वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का भी पुण्य कमा लेने का मौका नहीं छोड़ते हैं। महाकुंभ के अंतिम स्नान तक प्रदेश की आबादी से दोगुना श्रद्धालु प्रयागराज पहूंच चुके होंगे॥ यह विश्व रिकार्ड है, जो यदि कभी टूटेगा भी तो किसी कुंभ में ही टूटेगा॥

अजय कुमार, लखनऊ

उत्तर प्रदेश आजकल महाकुंभमय हो रखा है। हर तरफ एक जैसा नजारा है। कोई महाकुंभ में डुबकी लगाकर अपने आप में धन्य महसूस कर रहा है तो कोई डुबकी लगाने के लिये आतुर है, जिसको जैसा मौका मिल रहा है वह उस हिसाब से संगम नगरी प्रयागराज की तरफ प्रस्थान कर रहा है। प्रयागराज में साधू–संतो का तो जमावाड़ा है ही यहा पहुंचनें वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जो श्रद्धालू महाकुंभ पहुंचते हैं वह वाराणसी में बाबा विश्वनाथ और अयोध्या में रामलला के दर्शन करने का भी पुण्य कमा लेने का मौका नहीं छोड़ते हैं। महाकुंभ के अंतिम स्नान तक प्रदेश की आबादी से दोगुना श्रद्धालु प्रयागराज पहूंच चुके होंगे। यह विश्व रिकार्ड है, जो यदि कभी टूटेगा भी तो किसी कुंभ में ही टूटेगा। हाल यह है महाकुंभ की व्यवस्था देखने और इस आयोजन को शांतिपूवर्क सम्पन्न कराने के लिये योगी सरकार और शासन–प्रशासन सब के सब एक पैर पर खड़े नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो महाकुंभ परिक्षेत्र में पत्ता भी हिलता है तो एलर्ट मोड में आ जाते हैं। योगी की तो पूरी की पूरी कैबिनेट ही प्रयागराज पहुंच जाती है। सबसे खास बात यह है कि जितने भी श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से अधिक मुख्यमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, जिसके राजनैतिक निहितार्थ भी कम नहीं हैं। आज की तारीख में हिंदुत्व के नजरिये से योगी बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता बन गये हैं। इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी तक को पीछे छोड़ दिया है। सफल महाकुंभ में आग लगने की घटना और सबसे बड़े मौनी अमस्या के अमृत स्नान के दिन मची भगदड़ में श्रद्धालुओं की मौत की घटना से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ व्यथित भी दिखे, लेकिन जल्द ही सब कुछ सुचारू कर लिया गया और साधू संतों से लेकर आम श्रद्धालु तक आराम से स्नान करते दिखे।

महाकुंभ का मोह और इस दौरान संगम में डुबकी लगाने के लिये वह लोग तो व्याकुल हैं ही जो सनातन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पूरी दुनिया से लोग महाकुंभ के आकर्षण में प्रयागराज खिचे चले आ रहे हैं। यह लोग सनातन के बारे में अधिक से अधिक जानने को व्याकुल हैं। सबसे खास बात यह है कि महाकुंभ की आस्था अखिलेश यादव जैसे उन नेताओं को भी यहां खींच लाई है जिनका योगी और बीजेपी से छत्तीस का आकड़ा रहता है, लेकिन इस मौके पर भी अखिलेश राजनीतिक बातें करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि यह बड़ा आयोजन है। हमें याद है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब हमें कुंभ कराने का मौका मिला था। तब हमने कम संसाधन में इसे बेहतर तरीके से कराया था। यह बात तमाम स्टडी कहती हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी भी कहती है। अपनी सरकार के समय सफल कुंभ का दावा करते हुए अखिलेश ने पूर्व नगर

महाकुंभ का मोह और इस दौरान संगम में डुबकी लगाने के लिये वह लोग तो व्याकुल हैं ही जो सनातन धर्म का पालन करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी पूरी दुनिया से लोग महाकुंभ के आकर्षण में प्रयागराज खिचे चले आ रहे हैं। यह लोग सनातन के बारे में अधिक से अधिक जानने को व्याकुल हैं। सबसे खास बात यह है कि महाकुंभ की आस्था अखिलेश यादव जैसे उन नेताओं को भी यहां खींच लाई है जिनका योगी और बीजेपी से छत्तीस का आकड़ा रहता है।

विकास मंत्री और 2013 में कुंभ के आयोजन की जिम्मेदारी संभालने वाले आजम खान की तारीफ भी की। अखिलेश ने कहा उन्होंने काफी सीमित संसाधनों के सहारे कुंभ का यादगार बनाया था। वहीं अखिलेश के संगम स्नान करने पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव देर आए दुरुस्त आए। हरिद्वार में गंगा स्नान और महाकुंभ स्नान के बाद उम्मीद है कि अब आस्था को चोट पहुंचाने वाले बयानों से बचेंगे। केशव ने कहा कि महाकुंभ की विशेषता अनेकता में एकता है। जो सपाई और कांग्रेसी अब भी महाकुंभ को लेकर मानसिक और दृष्टि दोष से ग्रसित हैं। वे इलाज कराएं या न कराएं पर महाकुंभ स्नान जरूर करें। इसके साथ ही कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। ओपी राजभर ने कहा कि कल तक कुंभ की निंदा करने वाले लोग आज कुंभ में जा रहे हैं। यह संविधान की देन है।

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने तो महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद यहां की व्यवस्था को लेकर योगी सरकार पर हमला बोला वहीं कांग्रेस ने तो महाकुंभ पर ही प्रश्न चिंह खड़ा कर दिया। औसत प्रतिदिन जब महाकुंभ में करीब 95 लाख लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं. तब प्रयागराज से 925 किमी दूर, मध्य प्रदेश के महू यानी संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर की जन्मस्थली पर कांग्रेस की 'जय बापू, जय भीम, जय

संविधान रैली' में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां तक कह दिया, 'गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है, क्या भरपेट खाना मिलता है।' इस पर बुद्धीजीवियों का कहना है कि कांग्रेस को न तो हिन्दू धर्म रास आता है न यही दिखता है कि महाकुंभ से कैसे रोजगारों का सृजन हो रहा है। ऐसा लगता है कि गैर बीजेपी दलों के नेताओं को डर सता रहा है कि महाकुंभ के चलते कहीं उनकी हिन्दुओं को बांटों और राज करो वाली मुहिम को झटका नहीं लग जाये। महापुरूषों की जन्मस्थली प्रयागराज में आजकल सिर्फ और सिर्फ हिन्दुत्व ही नजर आ रहा है। यहां न कोई अगड़ा है और न कोई पिछड़ा या दलित।

बात खड़गे के महाकुंभ से लोगों के पेट नहीं भरने वाले बयान की कि जाये तो इसका जबाव सीएम योगी आदित्यनाथ से बेहतर कौन दे सकता है, जबकि योगी पहले ही कह चुके हैं कि एक पर्यटक या श्रद्धालु जब यूपी आता है तो ट्रेन, बस, टैक्सी या प्लेन का उपयोग करता है। होटल, टेंट या धर्मशाला में रुकता है। होटल, रेस्टोरेंट या ढाबे पर खाना खाता है, कुछ खरीदारी भी करता है। इस तरह वह औसतन पांच हजार रुपये खर्च करता है। प्रयागराज महाकुंभ मेला में 40 करोड़ लोगों के आने का अनुमान है। ऐसे में देश–प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अकेले महाकुंभ दो लाख करोड़ रुपये का योगदान देगा। महाकुंभ आस्था, आधुनिकता और स्वच्छता का मॉडल बनेगा।

खैर, बात बीजेपी के भीतर की कि जाये तो महाकुंभ का भव्य आयोजन करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के सबसे बड़े हिन्दुत्व वाले पोस्टर मैन बन गये हैं। योगी के खिलाफ पार्टी के अंदर यदाकदा जो विरोध के स्वर सुनाई पड़ते थे, वह भी फिलहाल ठंडे पड़ गये हैं। योगी की जो तस्वीर उभर रही है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि 2017 वाले योगी जी 2025 में काफी बदल चुके हैं।

2017 में भले ही योगी को मोदी और शाह की मेहरबानी से सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया था, लेकिन अब योगी को 'हाथ' लगाना किसी के बस की बात नहीं है। 2017 के विधान सभा चुनाव से पूर्व तक जो बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य मुख्यमंत्री पद के सबसे बड़े दावेदार थे, वह अब योगी से काफी पीछे खिसक गये हैं। केशव ने भी देर से ही सही (2022 के विधान सभा चुनाव के बाद) योगी को अपना नेता मान लिया है। अब वह विरोध की भाषा नहीं बोलते हैं। 2027 के यूपी विधान सभा चुनाव भी संभवता योगी के नेतृत्व में ही लड़ा जायेगा।

ऐसा इसलिये भी है क्योंकि आज भी योगी राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की पहली पसंद हैं। कुछ लोग तो 2029 के आम चुनाव में योगी को प्रधानमंत्री के फेस के रूप में भी देख रहे हैं। यही योगी की सियासी पूंजी है। मोदी कैबिनेट के दिग्गज मंत्री भी महाकुंभ में डुबकी लगाने के बाद कसीदे पढ़ते नजर आये। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह,गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ में सपरिवार स्नान कर चुके हैं। दस फरवरी को राष्ट्रपति और पांच फरवरी को प्रधानमंत्री के महाकुंभ आने

यूपीआई पेमेंट करने का तरीका बदला, अब ट्रांजेक्शन आईडी केवल अल्फान्यूमेरिक

- 1 फरवरी 2025 से यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी में विशेष वर्णों की अनुमति नहीं होगी।
- यूपीआई ऐप्स को 35–अक्षरों वाली अल्फान्यूमेरिक आईडी का पालन करना अनिवार्य होगा।
- उपयोगकर्ताओं को सुनिश्चित करना होगा कि उनका यूपीआई ऐप अपडेट रहे ताकि भुगतान में कोई बाधा न आए।

यदि आपका यूपीआई ऐप अभी भी विशेष अक्षरों वाली ट्रांजेक्शन आईडी जेनरेट करता है, तो 1 फरवरी 2025 के बाद आपके यूपीआई भुगतान असफल हो सकते हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने इस संबंध में घोषणा की है। डिजिटल भुगतान क्षेत्र में 31 जनवरी 2025 एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। एनपीसीआई ने बताया है कि 1 फरवरी 2025 से यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) प्रणाली में ट्रांजेक्शन आईडी को लेकर एक नया नियम लागू होगा। इस नियम के अनुसार, अब विशेष अक्षरों वाली ट्रांजेक्शन आईडी स्वीकार नहीं की जाएंगी। यह बदलाव उन सभी यूपीआई ऐप्स को प्रभावित करेगा जो अभी तक इस मानक का पालन नहीं कर रहे हैं। एनपीसीआई के नए दिशानिर्देशों के अनुसार, यूपीआई ट्रांजेक्शन आईडी केवल अल्फान्यूमेरिक होनी चाहिए। यदि किसी ट्रांजेक्शन आईडी में /, रु, –, :, या अन्य विशेष अक्षर होंगे, तो उस भुगतान को अस्वीकार कर दिया जाएगा। यह कदम यूपीआई प्रणाली को अधिक संगठित, सुरक्षित और सुचारू बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा, ट्रांजेक्शन आईडी की लंबाई 35 अक्षरों तक सीमित कर दी गई है, जिससे सभी यूपीआई लेन–देन में एकरूपता बनी रहे और तकनीकी त्रुटियों की संभावना कम हो।

एनपीसीआई क्या है?

नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों का संचालन और प्रबंधन करता है। इसकी स्थापना 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक और भारतीय बैंक संघ के सहयोग से की गई थी।

यूपीआई सिस्टम में यह बदलाव क्यों जरूरी है?

- लेन–देन को अधिक संगठित बनाना– भारत में 200 से अधिक यूपीआई ऐप्स उपलब्ध हैं, और हर ऐप का ट्रांजेक्शन आईडी बनाने का तरीका अलग है। यह नया नियम लेन–देन को ट्रैक करने को आसान बनाएगा।
- सिस्टम की दक्षता बढ़ाना– विशेष अक्षरों को हटाने से यूपीआई लेन–देन की प्रोसेसिंग तेज और त्रुटिरहित होगी।
- सुरक्षा सुनिश्चित करना– कुछ विशेष अक्षर तकनीकी त्रुटियों और सुरक्षा खामियों का कारण बन सकते हैं। यह बदलाव यूपीआई लेन–देन को और सुरक्षित बनाएगा।

यूपीआई भुगतान संबंधी समस्याओं से कैसे बचें?

- अपने यूपीआई ऐप की जांच करें– यह सुनिश्चित करें कि आपका यूपीआई ऐप नए नियमों के अनुरूप ट्रांजेक्शन आईडी बना रहा है।
- ऐप को अपडेट करें– यदि आपका यूपीआई ऐप पुराने संस्करण पर चल रहा है, तो इसे तुरंत अपडेट करें।
- उचित यूपीआई सेवा का चयन करें– यदि आपका मौजूदा यूपीआई ऐप नए नियमों का पालन नहीं कर रहा है, तो किसी अन्य विश्वसनीय यूपीआई ऐप का उपयोग करें।

यूपीआई सेवा प्रदाताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण तकनीकी बदलाव होगा।

ओंगो के कार्यकारी उपाध्यक्ष आलोक सिंह का मानना है कि 35–अंकीय अल्फान्यूमेरिक ट्रांजेक्शन आईडी से लेन–देन को ट्रैक करना आसान होगा और रिकॉर्ड रखने में पारदर्शिता बढ़ेगी। एनटीटी डेटा के राहुल जैन के अनुसार, यह कदम यूपीआई प्रणाली के मानकीकरण और सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यूपीआई उपयोगकर्ताओं के लिए क्या करना जरूरी है?

भारत में डिजिटल भुगतान की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है, और यूपीआई सबसे पसंदीदा भुगतान प्रणाली बन चुका है। इसलिए, यह आवश्यक है कि उपयोगकर्ता इस बदलाव के लिए समय रहते खुद को तैयार करें।

यदि आप यूपीआई से भुगतान करते हैं, तो अपने यूपीआई ऐप की तुरंत जांच करें कि क्या वह एनपीसीआई के नए दिशानिर्देशों का पालन कर रहा है। यदि नहीं, तो जल्द से जल्द ऐप को अपडेट करें या किसी अन्य विश्वसनीय यूपीआई सेवा का उपयोग करें।

क्या दलितों का मोहभंग हो रहा है भाजपा से

दलितों के सबसे बड़े आइकन बाबा साहेब डश्व अम्बेडकर हैं और विपक्ष ये नेगेटिव सेट करने में कामयाब रहा कि बीजेपी अगर चार सौ का आंकड़ा छू लेती है तो वह संविधान बदल देगी। देश की बहुसंख्यक दलित-बहुजन आबादी के लिए संविधान सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। इस आबादी ने हमेशा ये माना है कि यह संविधान ही है जिसने उन्हें समाज में सदियों से चल आ रहे जातिगत भेद-भाव से मुक्ति दिलाई है।

अजय श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश

2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों ने बड़े बड़े राजनीतिक पंडितों को चौका दिया था। एक तरफ भाजपा के नेता चार सौ पार का नारा दे रहे थे तो दूसरी तरफ मीडिया भी ये मान कर चल रहा था कि एनडीए चार सौ आस–पास ही रहेगी मगर जब परिणाम आया तो बीजेपी अपने दम पर बहुमत का आंकड़ा भी न छू सकी। हार के कारणों का पोस्टमार्टम मीडिया के सभी वर्गों में किया गया और कारण ये निकलकर आया कि दलितों ने भाजपा के प्रति विद्रोही रूख अख्तियार कर लिया है। प्रधानमंत्री ने चुनाव अभियान के दौरान जनता से कहा कि "हम अगली सरकार में कुछ बड़े फैसले लेना चाहते हैं इसलिए हमें मजबूत बहुमत चाहिए।"

दलितों के सबसे बड़े आइकन बाबा साहेब डॉ अम्बेडकर हैं और विपक्ष ये नेगेटिव सेट करने में कामयाब रहा कि बीजेपी अगर चार सौ का आंकड़ा छू लेती है तो वह संविधान बदल देगी। देश की बहुसंख्यक दलित–बहुजन आबादी के लिए संविधान सशक्तिकरण का प्रतीक भी है। इस आबादी ने हमेशा ये माना है कि यह संविधान ही है जिसने उन्हें समाज में सदियों से चल आ रहे जातिगत भेद–भाव से मुक्ति दिलाई है। संविधान के माध्यम से छूआछूत को दूर करने में मदद मिलेगी। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, शरद पवार, स्टालिन आदि बडे नेता ष्संविधान खतरे मेंष मुद्दे को प्रमुखता से उठाया और दलितों को लगा कि अगर संविधान बदला गया तो उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराएगा। दलितों का बडा हिस्सा विकल्प की तलाश में था और उन्होंने विपक्ष को चुना।

गौरतलब है कि देश में 156 सीटें ऐसी हैं, जहां दलित वोट काफी संख्या में हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो इस चुनाव में 156 सीटों में से 93 सीटें इस बार विपक्षी गठबंधन ने और 57 सीटें एनडीए ने जीती हैं। दलित वोट वाली 156 सीटों ने इस बार विपक्ष को 2019 के लोकसभा चुनाव के तुलना में 53 सीटों का फायदा कराया है। वहीं एनडीए को 34 सीट का नुकसान हुआ। बीजेपी ने 2019 में 32 प्रतिशत दलित वोट प्राप्त किये थे लेकिन 2024 में ये आंकड़ा घटकर 29 प्रतिशत हो गया। यह गिरावट भले ही मामूली दिखे, लेकिन यह दलितों के बीच बीजेपी के समर्थन में एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है।

2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला। समाज के सभी वर्गों ने बहुत उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, कारण वो कांग्रेस और उसके सहयोगियों के भ्रष्टाचार से ऊब चुके थे और वे बदलाव चाहते थे। दलितों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की उनके बीच उपस्थिति को एहतराम किया और पहली बार बसपा को छोड़कर एनडीए उम्मीदवारों को जिताने का काम किया। समर्थन का आलम ये था कि गैर जाटव वर्ग तो पूरी तरह से बीजेपी के सपोर्ट में आ गया था और जाटव मतदाता जो मायावती के प्रति अंधभक्त थे उसने भी बहुत हद तक पाला बदल लिया।

दलित चिंतक और लेखक रामदास कहते हैं कि दलितों का पढ़ा–लिखा तबका ये जानता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा मूल रूप से ब्राह्मणवादी संस्कृति में रचे बसे हैं। दलितों की गाय–भैंस–सुअर खाने जैसी जरूरतें और आदतें हैं। वो वेदों के बाहर के

देवताओं की पूजा करते हैं, जो शराब और मुर्गे–मुर्गियों का भोग लगाते हैं। ये बातें ब्राह्मणवादी ढांचे को कई बार नकारती हैं और संघ की संस्कृति के लिए समस्या पैदा करती हैं। दलितों के हीरो अंबेडकर, ज्योति बाई फूले, कांशीराम जैसे दलित हैं जो अभिजात्य वर्ग को गाली देते थे, उनकी पूजा–पद्धति पर सवाल उठाते थे। उनका मूल विरोध ब्राह्मणवादी संस्कृति और सामंतवादी व्यवस्था से था।

रामदास कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन के दौरान जब जय श्रीराम का नारा लगता था तब मान्यवर कांशीराम एक कहानी सुनाया करते थे कि अयोध्या के राजा रामचंद्र जी के राज्य में एक ब्राह्मण का लड़का अचानक मर गया। ब्राह्मण अपने लड़के के शव को लाकर राजद्वार पर डाल दिया और विलाप करने लगा। उसका आरोप था कि अकाल मृत्यु का कारण राजा का कोई दुष्कृत्य है। मुनियों की परिषद ने इस पर विचार करके निर्णय लिया कि राज्य में कहीं कोई अनधिकारी तप कर रहा है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा में अकाल मृत्यु होती है। द्वापर में शुद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म है। निश्चय ही आपके राज्य की सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शुद्र तपस्या कर रहा है। उसी के कारण बालक की मृत्यु हुई है। आप अपने राज्य में खोज करिए और जहां कोई दुष्ट कर्म होता दिखाई दे वहां उसे रोकने का यत्न कीजिए। राजा रामचंद्र जी ने दलित शंबूक ऋषि को तप करते हुए देखा और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। कांशीराम दलितों को ये बताने की कोशिश करते थे और ब्राह्मणवादी व्यवस्था में दलितों की स्थिति जानवर के बराबर भी नहीं है।

दलितों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नजरिया 30 नवंबर 1949 को उनके मुखपत्र ऑर्गनाइजर के संपादकीय से समझा जा सकता है जिसमें लिखा गया कि ष्भारत का संविधान विदेशी है इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है क्योंकि इसमें मनु की संहिताएं नहीं हैं। इसलिए हमें भारत का संविधान स्वीकार नहीं है।ष डा. आंबेडकर मनु संहिता के सबसे बड़े आलोचक थे और अतीत में संघ ने हमेशा मनु संहिता को हीं अपनी विचारधारा से जोडा था। दूसरा उदाहरण दलितों के बीच हिंदुत्व का पोषण करने के लिए संघ

गौरतलब है कि देश में 156 सीटें ऐसी हैं, जहां दलित वोट काफी संख्या में हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो इस चुनाव में 156 सीटों में से 93 सीटें इस बार विपक्षी गठबंधन ने और 57 सीटें एनडीए ने जीती हैं। दलित वोट वाली 156 सीटों ने इस बार विपक्ष को 2019 के लोकसभा चुनाव के तुलना में 53 सीटों का फायदा कराया है। वहीं एनडीए को 34 सीट का नुकसान हुआ।

ने ष्सामाजिक समरसता मंच (1983) स्थापित किया। दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक मानववाद का सिद्धांत दिया इसका अर्थ है जाति भेद बनाए रखते हिंदू एकता स्थापित करना। संघ ने पिछडी जातियों में बीच कुछ लडाका जातियों के लोगों को इकठ्ठा कर बजरंग दल का निर्माण किया। पिछडी जातियों के लोग अगड़ी जातियों से यदा–कदा ही संघर्ष करते थे लेकिन वे दलितों के प्रति आक्रमक थे। पिछड़ी जातियों में कुछ लडाका जातियों को उन्होंने धर्म रक्षक में तब्दील कर दिया। रामायण के कुछ कैरेक्टर जैसे हनुमान, निषादराज, शबरी, नल–नील, अंगद, जामवंत जैसे चरित्रों को दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के पूर्वज बताकर उन्हें सेवक और बलिदानी बनाया गया।

कालांतर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये समझ गया था कि बिना पिछड़ों और दलितों को इकठ्ठा किये वो हिंदूत्व का एजेंडा लागू नहीं कर सकता है। इसके लिए उन्होंने बहुत सार्थक प्रयास किया और 2014 के लोकसभा चुनाव में इसका परिणाम भी दिखा। दलितों का रहनुमा कहलाने वाला बहुजन समाज पार्टी दलितों की रिजर्व सीट पर अपना खाता भी नहीं खोल पाई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी भी दहाई में सिमट गई। फिर क्या हो गया कि दस साल में दलितों का मोहभंग भाजपा से होने लगा। इसके बहुत से कारण हैं कुछ कारणों पर विचार बेहद जरूरी भी है।

सबसे पहले देश के सबसे बड़े सूबे यूपी की बात करते हैं। दलितों पर अत्याचार के मामले में यूपी सबसे अव्वल रहा है। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सहारनपुर के बसपा सांसद हाजी फजलुर्रहमान के एक सवाल पर कहा कि यूपी में दलितों के ऊपर 36,467 मामले प्रकाश में आए हैं। बिहार में 20,973 और राजस्थान में 18,418 मामले दर्ज किए गए हैं। देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तीन साल में 139045 अनुसुचित जाति पर अत्याचार के मुकदमे दर्ज हुए हैं। साल 2018 में 42793, 2019 में 45961 और 2020 में 50291। इनमें से अधिकांश राज्य बीजेपी शासित हैं या उसमें सहयोगी दल के मुख्यमंत्री हैं जो बकौल रामदास दलितों पर अत्याचार रोकने में नाकाम रहे हैं। यही मुख्य वजह दलितों के मोहभंग की है। 2014 में नरेंद्र मोदी ने दलितों को नौकरी देने का वायदा किया था जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। देश में सरकारी नौकरी के बदले अधिकतर काम आउटसोर्सिंग से हो रहे हैं, जिसमें आरक्षण का फार्मूला लागू नहीं होता। पिछड़े और दलित समाज में इसका बहुत खराब मैसेज गया है। दलित समाज संविदा की नौकरी में आरक्षण की मांग कर रही है जो सरकार देने में टालमटोल कर रही है।

दलितों पर अत्याचार, संविधान के मुद्दे, रोजगार के अलावा आम जिंदगी की दुश्वारियों ने भी अहम रोल निभाया है। दलित चिंतक और विचारक रामदास कहते हैं कि दलित जिस उम्मीद के साथ भाजपा से जुड़े थे वो टूटती हुई दिख रही है। वे कहते हैं संघ ने डॉ अम्बेडकर को पूजने का ढ़ोंग तो किया लेकिन उनके संविधान और विचारों को खत्म करने की रोज कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष रहे विवेक देवराय से लेकर कर्नाटक के सांसद अनंत कुमार हेगड़े खुलेआम संविधान को बदलने का ऐलान कर रहें हैं। दलितों को लेकर भाजपा में मंथन जारी है और भाजपा का थिंक टैंक ये अच्छे से समझता है कि अगर दलितों ने उनसे मुंह मोड़ा तो दिल्ली में हुकूमत करना टेढ़ी खीर साबित होगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के नेता लगातार इस मुद्दे पर बैठक कर रहें हैं और बहुत जल्द ही दलितों को खुश करने के लिए कोई प्लान धरातल पर उतारा जाएगा अब चाहे वो दलितों को भरमाने के लिए ही क्यों न हो।

क्या पलायन के असली जिम्मेदार जगमोहन थे?

जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन अपनी किताब "दहकते अंगारे" में लिखते हैं कि "वह रात मेरे जीवन की सबसे अजीब रात थी। मैं सोने ही वाला था कि मेरे बिस्तर के दोनों तरफ रखे टेलीफोन एक साथ बजने लगे। टेलीफोन के दूसरी तरफ से आतंक से कांपती आवाजें आ रहीं थीं आज की रात हमारी आखिरी रात है। सुबह तक हम कश्मीरी पंडितों को मार दिया जाएगा।

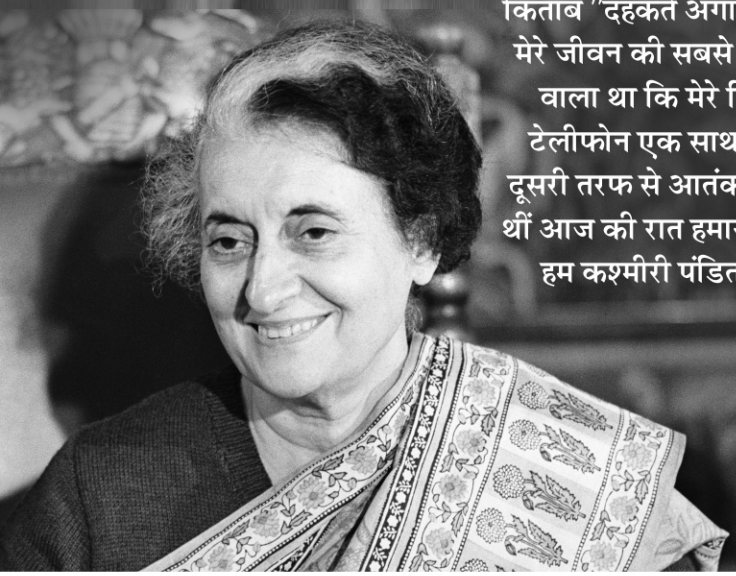

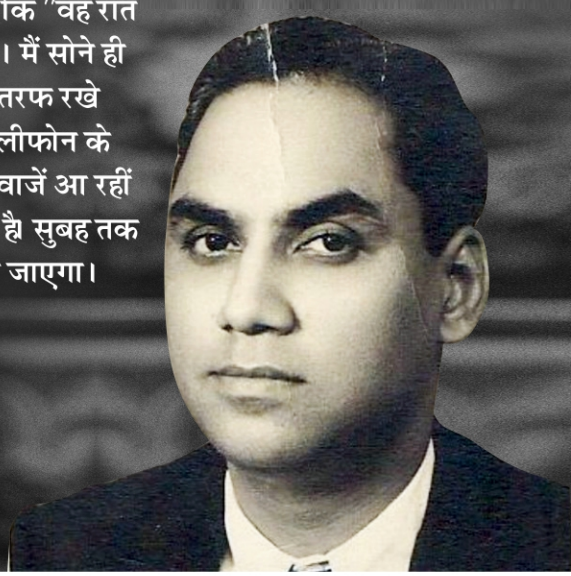

अजय श्रीवास्तव
वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश

जब कांग्रेस को पराजित कर केंद्र में वी. पी. सिंह की सरकार बनी थी, तब सरकार को एक तरफ दक्षिणपंथी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ उनकी धुर विरोधी वामपंथी दल समर्थन कर रहे थे। वी. पी. सिंह को दोनों की सुननी पड़ रही थी। उन दिनों जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर पहुंच चुका था। दरअसल इसकी शुरुआत तो बहुत पहले हो चुकी थी, मगर परवान 1987 के विधानसभा चुनाव के बाद चढ़ा। इस चुनाव में उनकी बुरी तरह हार हुई थी, जो पाकिस्तान परस्त थे। उन्होंने ये आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई है। चुनाव परिणाम से अलगाववादी नेताओं के अलावा पाकिस्तान भी चिंतित था क्योंकि उसे डर सता रहा था कि अगर कश्मीरी अवाम ने शांतिपूर्ण ढंग से सोचना शुरू कर दिया तो उसका आतंकवाद का एजेंडा धरा का धरा रह जाएगा। पाकिस्तान के सहयोग से अलगाववादियों ने एक चरमपंथी संगठन 'जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट' (जेकेएलएफ) का गठन किया, जिसका उद्देश्य हथियार के दम पर कश्मीर को भारत से आजाद करना था।

जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं के खिलाफ नफरत के बीज 1986 में ही पड़ चुके थे, जब फारूक अब्दुल्ला के साले गुलाम मोहम्मद शाह ने अपने बहनोई को बेदखल कर सत्ता छीन ली थी। उनको जानने वाले कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ कश्मीरी मुसलमानों को भड़काना शुरू कर दिया

था। गुलाम मोहम्मद शाह अच्छी तरह समझ गए थे कि उन्हें ज्यादा दिन सत्ता में नहीं रहने दिया जाएगा। उन्हें लगा कि कुछ विवादित मुद्दों को उठाकर वे कश्मीरी मुसलमानों के हीरो बन सकते हैं। उनके एक विवादित निर्णय से दोनों समुदाय के लोगों के बीच खाई और चौडी हो गई। शाह सरकार ने एक विवादित निर्णय ये लिया कि जम्मू के न्यू सिविल सेक्रेटेरिएट एरिया में एक पुराने मंदिर को गिराकर भव्य शाह मस्जिद बनवाई जाएगी। चूंकि वो पुराना मंदिर था, और लोग वहां पूजा–पाठ के लिए जाते थे, इसको तोड़ने के सरकार के निर्णय का विरोध होना शुरू हो गया। रोज प्रर्दशन होते और गिरफ्तारियां आमबात हो गई थीं।

गौरतलब है कि इंदिरा गांधी के ही कहने पर तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी। फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करने के लिए ही संजय गांधी के बेहद निकटवर्ती जगमोहन को राज्यपाल बनाया गया था, दरअसल इंदिरा गांधी के रिश्ते के भाई बीजू नेहरू उन दिनों जम्मू–कश्मीर के राज्यपाल हुआ करते थे, और वे अब्दुल्ला परिवार के बेहद निकट थे। उन्होंने फारूक अब्दुल्ला सरकार को बर्खास्त करने से मना कर दिया था तब बीजू नेहरू को हटाकर कडक जगमोहन को राज्यपाल बनाया गया।

मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के इस निर्णय के कारण हिंदू समाज आंदोलित था। गुलाम मोहम्मद शाह ने ये कहकर दोनों धर्मावलंबियों के बीच और वैमनस्य फैला दिया कि हिंदुओं के कारण इस्लाम खतरे में है। ये बात वहाँ के आम जनमानस के दिलो–दिमाग में बैठ गई और साम्प्रदायिक दंगे शुरू हो गए। साउथ कश्मीर और सोपोर में तो हालत बद से बदतर हो जा रहे थे, सरकार दंगा रोकने में नाकाम थी या साजिशन रोकना नहीं चाहती थी। राज्यपाल जगमोहन ने दंगा रोकने में विफलता का आरोप मढ़कर 12 मार्च 1986 को शाह सरकार को बर्खास्त कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया।

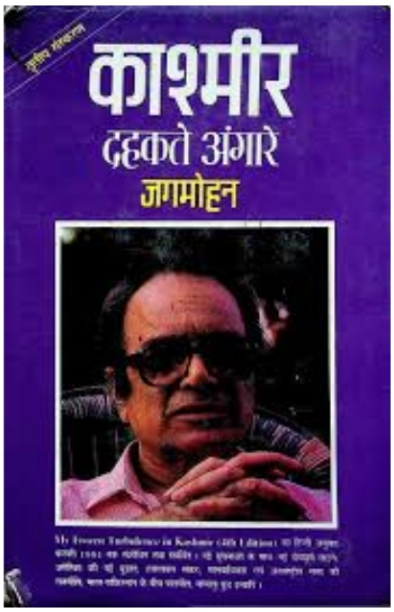

गौरतलब है कि इंदिरा गांधी के ही कहने पर तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन ने फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर गुलाम मोहम्मद शाह को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाई थी। फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करने के लिए ही संजय गांधी के बेहद निकटवर्ती जगमोहन को राज्यपाल बनाया गया था,

गुलाम मोहम्मद शाह ने जो जहर बोया था उसका परिणाम 14 सितंबर 1989 को पहली बार तब देखने को मिला जब भाजपा नेता पंड़ित टीकालाल टपलू को सबके सामने गोलियों से भून दिया गया। हत्यारे स्थानीय लड़के थे जो नए नए जेकेएलएफ में शामिल हुऐ थे, कोई भी गवाही देने सामने नहीं आया। उसके बाद रिटायर्ड जज नीलकंठ गंजू की हत्या हो गई। जज नीलकंठ गंजू ने जेकेएलएफ के नेता मकबूल भट्ट को मौत की सजा सुनाई थी। गंजू की पत्नी का अपहरण कर लिया गया जो फिर कभी नहीं मिली। वकील प्रेमनाथ भट्ट की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 13 फरवरी 1990 को श्रीनगर के टेलीविजन केंद्र के निदेशक लासा कौल की हत्या हो गई। ये बडे लोग थे छोटे लोगों की तो कोई गिनती ही नहीं थी।

19 जनवरी 1990 को घाटी के सभी मस्जिदों से ये एलान किया गया कि "असि गछि पाकिस्तान, बटव रोअर त बटनेव सानष (हमें पाकिस्तान चाहिए, पंड़ितों के बगैर, पर उनकी औरतों के साथ)। इस ऐलान के बाद तो कश्मीरी पंडितों की हत्या और उनकी बहू–बेटियों के साथ बलात्कार का जो सिलसिला घाटी में शुरू हुआ वो कई सालों तक चला।

जम्मू–कश्मीर के पूर्व राज्यपाल जगमोहन अपनी किताब "दहकते अंगारे" में लिखते हैं कि "वह रात मेरे जीवन की सबसे अजीब रात थी। मैं सोने ही वाला था कि मेरे बिस्तर के दोनों तरफ रखे टेलीफोन एक साथ बजने लगे। टेलीफोन के दूसरी तरफ से आतंक से कांपती आवाजें आ रहीं थीं आज की रात हमारी आखिरी रात है। सुबह तक हम कश्मीरी पंडितों को मार दिया जाएगा।"

जगमोहन ने उसी रात सेना को जम्मू–कश्मीर में तैनात कर दिया। सुबह होते होते सैकड़ों कश्मीरी पंडितों को मार दिया गया, उनके घरों को जलाया गया और अलगाववादियों ने उनकी बहू बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार कर मानवता को शर्मसार किया था। राज्यपाल जगमोहन अगर सेना न बुलाते तो लाखों कश्मीरी पंडितों को मार दिया जाता। जगमोहन के कारण ही कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित घाटी से निकालकर राहत कैंपों में पहुँचाया गया था। राज्यपाल उन्हें मरने के लिए उनके घरों में कैसे छोड़ सकते थे, जब उन्माद अपने चरम पे था।

सैफुद्दीन सोज ने अपनी किताब में लिखा है कि घाटी से कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए जगमोहन जिम्मेदार थे। मेरे ख्याल से उनका ये आरोप बिल्कुल गलत है, अगर जगमोहन उन्हें सुरक्षित कैंपों में न रखते तो बहुत बडा कत्लेआम हो सकता था। उन दिनों कश्मीर पुलिस का साम्प्रदायीकरण हो गया था, वे आंतकियों को पकड़ने की कोशिश भी नहीं करते थे। अस्पतालों में हिंदुओं के साथ भेदभाव होता था। राज्यपाल के रूप में मैं जगमोहन की भूमिका की सराहना करता हूँ, उन्होंने कश्मीरी पंडितों को सुरक्षित कैंपों में पहुँचाकर मानवता का भला ही किया था।

दलितों को लुभाने के लिए कांग्रेस का नया अभियानः जय बापू, जय भीम

कांग्रेस ने 'जय बापू, जय भीम और जय संविधान' नामक अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान देशभर में कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा का माध्यम बन रहा है, जिसका उद्देश्य दलित समाज के बीच अपनी पुरानी पहचान को फिर से स्थापित करना है।

अजय कुमार, लखनऊ

कांग्रेस इन दिनों अपनी खोई हुई सियासी जमीन को दोबारा पाने के लिए जी–जान से जुटी हुई है। वर्षों से सत्ता के केंद्र में रही यह पार्टी, अब देश के हर हिस्से में अपने लिए जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में कांग्रेस ने 'जय बापू, जय भीम और जय संविधान' नामक अभियान की शुरुआत की है। यह अभियान देशभर में कांग्रेस के लिए एक नई ऊर्जा का माध्यम बन रहा है, जिसका उद्देश्य दलित समाज के बीच अपनी पुरानी पहचान को फिर से स्थापित करना है। इस अभियान का आगाज दिल्ली के सीलमपुर से हुआ, फिर कर्नाटक के बेलगाम में इसकी गूंज सुनाई दी और अब अगला पड़ाव डॉ. भीमराव आंबेडकर की जन्मस्थली महू है, जहां 28 जनवरी को एक विशाल जनसभा होने वाली है।

इस अभियान के जरिए कांग्रेस ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि वह दलित समाज के दिल और दिमाग में एक बार फिर जगह बनाना चाहती है। आजादी के शुरुआती वर्षों में कांग्रेस दलितों के लिए सबसे बड़ा सियासी मंच हुआ करती थी, लेकिन अस्सी के दशक में बसपा के उदय के बाद यह समीकरण पूरी तरह बदल गया। उत्तर भारत के कई राज्यों में दलित वोट कांग्रेस से खिसककर बसपा की झोली में चले गए। वहीं, पिछले कुछ दशकों में बीजेपी ने भी दलितों के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ने में सफलता हासिल की। 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने आरक्षण और संविधान जैसे मुद्दों के जरिए दलित समाज के बीच नई उम्मीदें जगाई थीं, और अब वह इस विश्वास को और मजबूत करने के लिए मैदान में उतर आई है।

कांग्रेस का यह कदम बसपा की राजनीति से प्रेरित नजर आता है। जिस तरह से बसपा ने नीला झंडा, हाथी का निशान और 'जय भीम' के नारों से अपनी पहचान बनाई थी, उसी राह पर अब कांग्रेस भी चलती दिख रही है। कांग्रेस नेता, जिनमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हैं, नीला अंगवस्त्र धारण कर मंच साझा कर रहे हैं और डॉ. भीमराव आंबेडकर की तस्वीरें मंच की शोभा बढ़ा रही हैं। जय भीम का नारा, जो कभी बसपा की पहचान हुआ करता था, अब कांग्रेस की सभाओं में गूंज रहा है।

डॉ. आंबेडकर की राजनीतिक और सामाजिक विरासत आज केवल दलितों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे भारत की राजनीति का केंद्र बन चुकी है। दलित समाज के लिए आंबेडकर एक प्रेरणा हैं, एक मसीहा हैं, और कांग्रेस इसे भलीभांति समझती है। यही वजह है कि आंबेडकर के नाम को लेकर कांग्रेस ने एक ठोस रणनीति बनाई है। बीजेपी नेता अमित शाह द्वारा आंबेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने इस मामले को लेकर न केवल बीजेपी पर निशाना साधा, बल्कि दलित समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की।

कांग्रेस का यह अभियान केवल एक राजनीतिक योजना नहीं है, बल्कि एक विचारधारा को फिर से जीवित करने की कोशिश है। यह अभियान उन दलितों

कांग्रेस के लिए यह समय निर्णायक है। दलित समाज के बीच अपनी खोई हुई जगह को पाने के लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी है। इस अभियान के तहत न केवल बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।

तक पहुंचने का प्रयास है, जो मायावती के नेतृत्व में बसपा से निराश होकर अब सपा या बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस का मानना है कि बसपा की कमजोर होती पकड़ के बाद दलित वोटर्स स्थायी रूप से किसी एक पार्टी से नहीं जुड़े हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास मौका है कि वह अपने पुराने कोर वोट बैंक को वापस हासिल कर सके।

2024 के लोकसभा चुनावों ने कांग्रेस के इस विश्वास को और मजबूत किया है। इन चुनावों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने दलित बहुल क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। बीजेपी, जिसने 2014 और 2019 में दलित वोटों पर बड़ा कब्जा जमाया था, इस बार कमजोर पड़ी। सीएसडीएस के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में बीजेपी को केवल 31: दलित वोट मिले, जो 2019 के मुकाबले 3: कम थे। वहीं, कांग्रेस और उसके सहयोगियों ने दलित वोटों में बड़ा हिस्सा पाया। इन चुनावों में दलित बहुल 156 लोकसभा सीटों में से 93 सीटें विपक्षी गठबंधन के खाते में गईं।

देश में दलित समाज की जनसंख्या का महत्व किसी से छिपा नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार, दलितों की आबादी 17 प्रतिशत है, जो 20 करोड़ से ज्यादा है। 543 लोकसभा सीटों में से 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन दलितों का सियासी प्रभाव 150 से अधिक सीटों पर देखा जाता है। ऐसे में दलित वोट किसी भी पार्टी के लिए सत्ता तक पहुंचने की कुंजी हो सकते हैं।

कांग्रेस के लिए यह समय निर्णायक है। दलित समाज के बीच अपनी खोई हुई जगह को पाने के लिए उसने पूरी ताकत झोंक दी है। इस अभियान के तहत न केवल बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की जा रही हैं, बल्कि स्थानीय स्तर पर भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। 28 जनवरी को महू में होने वाला कार्यक्रम इस अभियान का अहम हिस्सा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और अन्य प्रमुख नेता शामिल होंगे।

यह साफ है कि कांग्रेस दलितों को लुभाने के लिए पूरी तरह से बसपा की शैली को अपना रही है। इसके तहत पार्टी ने डॉ. आंबेडकर को अपने एजेंडे का केंद्र बनाया है और उनके नाम पर दलित समाज से संवाद स्थापित करने का प्रयास कर रही है। यह देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस का यह प्रयास कितना सफल होता है। लेकिन एक बात तय है, देश के बदलते सियासी परिदृश्य में दलित समाज के लिए कांग्रेस की यह कवायद एक नई सियासी दिशा तय कर सकती है।

अब थाईलैंड में भी समलैंगिक विवाह को मिली मान्यता, हाईप्रोफाइल गे कपल ने की शादी

थाईलैंड में कानून लागू होते ही एक हाई-प्रोफाइल गे कपल ने प्रस्तावित 100 समलैंगिक शादियों में से दूसरी शादी कर ली है। पहली शादी सुमाली सुदसेनेट (64) और थानाफोन चोखोंगसुंग (59) ने की।

जहां एक ओर भारत में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने के लिए वर्षों से संघर्ष जारी है, वहीं दूसरी ओर एशियाई देशों में इसे कानूनी मान्यता मिल रही है। अब थाईलैंड, जो लोगों का पसंदीदा पर्यटन स्थल है, में भी समलैंगिक विवाह कानून प्रभावी हो गया है। इस कानून के लागू होते ही एक हाई–प्रोफाइल गे कपल ने शादी की है। रिपोर्ट के अनुसार, इस कानून के लागू होने के बाद आज के दिन ही 100 से अधिक शादियां प्रस्तावित हैं। इनमें से पहली शादी सुमाली सुदसेनेट और थानाफोन चोखोंगसुंग ने बैंकॉक के बंगरक जिले में की।

समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला थाईलैंड एशिया का तीसरा और सबसे बड़ा देश बन गया है। 2024 में थाईलैंड की संसद ने इस विधेयक को पारित किया था, जिसके बाद स्ळठज्फ समुदाय में खुशी की लहर दौड़ गई। इस कानून में पति–पत्नी के स्थान पर 'व्यक्ति' शब्द का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही, समलैंगिक जोड़ों को बच्चों को गोद लेने और उत्तराधिकारी घोषित करने का अधिकार भी दिया गया है।

थाईलैंड में समलैंगिकता को लेकर भारत जैसे अन्य एशियाई देशों के समान विरोध था। ।ब्च की रिपोर्ट के अनुसार, कई स्ळठज्फ समुदाय के लोगों ने भेदभाव का सामना किया है। सेम–सेक्स मैरिज के लिए थाई कार्यकर्ता एक दशक से अधिक समय से संघर्ष कर रहे थे। हालांकि, तख्तापलट और बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के चलते यह प्रयास बार–बार असफल हो जाता था।

थाईलैंड के अभिनेता अपीवात पोर्श अपीवात्सायरी (49) और साप्पन्यो आर्म पैनाटकूल (38) ने बैंकॉक के एक रजिस्ट्री कार्यालय में शादी की। उन्हें विवाह प्रमाणपत्र भी दिया गया। शादी के दौरान यह कपल भावुक होकर रो पड़ा।

यह कानून सितंबर 2024 में थाईलैंड के राजा महा वजीरालोंगकोर्न द्वारा अनुमोदित किया गया था और 120 दिनों के बाद इसे लागू कर दिया गया। थाईलैंड अब दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है जिसने सेम–सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी है। यह देश स्ळठज्फ समुदाय के लिए सहिष्णुता और कानूनी अधिकारों के मामले में विश्व स्तर पर पहचाना जाता है। 2001 में नीदरलैंड ने समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता दी थी, ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश था। इसके बाद 20 से अधिक देशों ने इसे लागू किया। एशिया में ताइवान और नेपाल पहले ऐसे देश थे जिन्होंने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी, और अब थाईलैंड तीसरा देश बन गया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाले देशों में नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, अमेरिका, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, स्वीडन, मैक्सिको, पुर्तगाल, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चिली, जर्मनी सहित अन्य शामिल हैं। एशियाई देशों में अब नेपाल, ताइवान और थाईलैंड का नाम प्रमुख है।

सर्च रिपोर्ट के बगैर लोन मंजूर ना करें बैंक-सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बैंकों द्वारा बिना उचित टाइटल सर्च रिपोर्ट के संपत्ति से जुड़े लोन देने के मामले में सख्त रुख अपनाया है।

सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों द्वारा टाइटल सर्च रिपोर्ट के बिना संपत्ति आधारित लोन देने पर कड़ी आपत्ति जताई है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से एक मानकीकृत और व्यावहारिक ढांचा तैयार करने का अनुरोध किया है, ताकि लोन मंजूरी से पहले टाइटल सर्च रिपोर्ट की जांच अनिवार्य हो सके। कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषपूर्ण टाइटल सर्च रिपोर्ट पर आधारित लोन देने वाले बैंक अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाए और आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाए।

कोर्ट ने आरबीआई और अन्य संबंधित प्राधिकरणों से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि टाइटल सर्च रिपोर्ट की गुणवत्ता और मान्यता के लिए एक ठोस ढांचा तैयार हो। कोर्ट ने कहा, ष्बैंकों को लोन मंजूरी से पहले यह पक्का करना चाहिए कि संपत्ति के मालिकाना हक और कानूनी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो।ष साथ ही, टाइटल सर्च रिपोर्ट की गुणवत्ता बनाए रखने और इसकी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए शुल्क और लागत के मानक दिशानिर्देश बनाए जाने की भी बात कही गई।

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संपत्ति लेन–देन में कानूनी विवादों से बचने और सौदों को सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए टाइटल सर्च रिपोर्ट का महत्व बहुत अधिक है। यह रिपोर्ट संपत्ति के स्वामित्व की पुष्टि करती है और किसी भी विवाद या कानूनी दावे की जानकारी देती है। कोर्ट ने आगाह किया कि बिना सही टाइटल सर्च रिपोर्ट के लोन देना न केवल बैंकों के लिए वित्तीय जोखिम पैदा कर सकता है, बल्कि यह सार्वजनिक धन को भी खतरे में डालता है।

वर्तमान में, बैंकों को पैनल वकीलों द्वारा तैयार की गई टाइटल सर्च रिपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन इसमें मानकीकरण की कमी है, जिससे रिपोर्ट की गुणवत्ता में अंतर हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि विवादित संपत्तियों पर लोन मंजूरी के मामलों में बैंक अधिकारियों की लापरवाही से बैंकिंग प्रणाली की साख पर सवाल खड़े हुए हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि मजबूत टाइटल सर्च रिपोर्ट न केवल धोखाधड़ी रोकने में मददगार है, बल्कि यह संपत्ति के स्वामित्व को स्पष्ट कर किसी भी प्रतिकूल दावे का पता लगाने में सहायक है।

सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने भारतीय बैंकिंग क्षेत्र को अधिक पारदर्शिता और जिम्मेदारी की दिशा में कदम उठाने के लिए प्रेरित किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले से न केवल लोन प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि सार्वजनिक धन और ग्राहकों की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।

अब बैंकों को अपनी लोन प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे केवल पूरी और सटीक टाइटल सर्च रिपोर्ट के आधार पर ही लोन प्रदान करें। यह आदेश भारतीय बैंकिंग प्रणाली में सुधार की दिशा में एक अहम कदम है, जो यह संदेश देता है कि समय रहते सही कदम उठाना आवश्यक है।

मुंबई के सिद्धि विनायक मंदिर में ड्रेस कोड लागू: अन्य देशों के पूजास्थलों में भी लागू हैं कई नियम

मुंबई के लोकप्रिय श्री सिद्धिविनायक मंदिर में अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं। इन नियमों के अनुसार, मंदिर आने वाले भक्तों को भारतीय परिधान पहनने की सलाह दी गई है। मंदिर प्रशासन ने दिशा–निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भक्तों को शालीन और शरीर को ढकने वाले वस्त्र धारण करने होंगे। मंदिर प्रशासन द्वारा जारी इन नियमों को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। कुछ लोग इन नियमों की तुलना उत्तर भारत के मंदिरों में पहले से लागू सख्त ड्रेस कोड से कर रहे हैं, तो कुछ अन्य लोग विदेशों के धार्मिक स्थलों के नियमों का हवाला देते हुए इस पर अपनी राय रख रहे हैं।

सिद्धिविनायक मंदिर के नए नियम क्या हैं?

- श्री सिद्धिविनायक गणपति मंदिर ट्रस्ट द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के तहतः
- भक्तों को भारतीय परिधान पहनने की सलाह दी गई है।
- अगले हफ्ते से मंदिर में कटे–फटे ट्राउजर, छोटी स्कर्ट, या ऐसे कपड़े पहनकर आने की अनुमति नहीं होगी जो शरीर के हिस्सों को उजागर करते हैं।
- मंदिर ट्रस्ट ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि कई भक्तों ने अनुशासनहीनता और अनुचित कपड़ों को लेकर चिंता जताई थी।
- इस नियम का उद्देश्य मंदिर की पवित्रता बनाए रखना और सभी भक्तों के लिए एक अनुशासित वातावरण सुनिश्चित करना है।

देश के इन मंदिरों में पहले से लागू है ड्रेस कोड

बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन

- दिसंबर 2024 में वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में भी ड्रेस कोड लागू किया गया था।
- भक्तों को छोटे कपड़े, हाफ पैंट, और चमड़े की बेल्ट पहनने से परहेज करने को कहा गया था।

- मंदिर प्रबंधन ने इसके लिए प्रवेश द्वारों पर बैनर लगाए थे।

शिवगिरी मठ, केरल

- केरल के कई मंदिरों में पुरुषों के लिए बिना शर्ट के प्रवेश करने की परंपरा रही है।
- जब इस परंपरा को समाप्त करने की बात उठी, तो यह मुद्दा विवाद का कारण बन गया।
- केरल के मुख्यमंत्री ने इस बदलाव का समर्थन किया था।

उत्तर प्रदेश के मंदिरों में ड्रेस कोड

- मथुरा के राधा रानी मंदिर में स्कर्ट, फटी जींस और अभद्र कपड़ों पर रोक है।
- आगरा के कैलाश मंदिर में महिलाओं के लिए साड़ी और पुरुषों के लिए धोती–कुर्ता अनिवार्य किया गया है।
- अलीगढ़, बुलंदशहर और अन्य स्थानों के मंदिरों में भी ड्रेस कोड के नियम लागू हैं।

उत्तराखंड के मंदिरों में नियम

- बदरीनाथ, केदारनाथ, नैनीताल के कैंची धाम और हरिद्वार के दक्षेश्वर महादेव मंदिर में भक्तों के लिए मर्यादित वस्त्र अनिवार्य हैं।
- नीलकंठ महादेव और टपकेश्वर मंदिर में भी अमर्यादित कपड़ों पर रोक है।

भारत के अन्य मंदिरों में भी ड्रेस कोड

- तिरुपति बालाजी मंदिर (आंध्र प्रदेश): पुरुषों को धोती और महिलाओं को साड़ी पहनने की सलाह।
- गुरुवायुर कृष्ण मंदिर (केरल)रू पुरुषों को लुंगी और महिलाओं को साड़ी पहननी होती है।
- महाबलेश्वर मंदिर (महाराष्ट्र)रू जींस, पायजामा, बरमूडा पर रोक, धोती–साड़ी अनिवार्य।
- महाकाल मंदिर (मध्य प्रदेश)रू मर्यादित वस्त्र पहनने का नियम।

विदेशों में कहां लागू हैं ड्रेस कोड?

- फिलीपींसः बैसिलिका माइनोरे डेल सैंटो नीनो डी सेबू में ड्रेस कोड लागू।
- स्पेनः कैथेड्रल डी सेविया में अमर्यादित कपड़ों पर रोक।
- इटलीः चर्चों और कैथेड्रल में कंधे–घुटने ढकने वाले कपड़े अनिवार्य।
- जापानः पूजास्थलों में शरीर ढकने वाले वस्त्र आवश्यक।
- ब्रिटेनः चर्च ऑफ इंग्लैंड ने 2016 में एक धर्मगुरु को अनुचित कपड़ों के कारण बर्खास्त किया था।
- वैटिकन सिटीः 2010 में धार्मिक स्थलों में मर्यादित कपड़ों को अनिवार्य किया गया था।

मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में लागू नए ड्रेस कोड को लेकर चर्चाएं जारी हैं। देश और विदेश में कई धार्मिक स्थलों में पहले से ही इस तरह के नियम लागू हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह निर्णय मंदिरों की परंपरा और अनुशासन बनाए रखने के लिए लिया गया है।

दिल्ली में केजरीवाल को हराने के लिए कांग्रेस की सियासी चालें तेज

कांग्रेस के नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वह अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को किसी भी स्थिति में वश्वकओवर नहीं देने वाली। इसके लिए पार्टी ने अपनी ताकतवर रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने जहां एक ओर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने की योजना बनाई है, वहीं दूसरी ओर पार्टी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के खिलाफ खुली जंग छेड़ी है।

अजय कुमार, लखनऊ

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सियासी हलचल तेज हो चुकी है। यह चुनाव भारतीय राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, खासकर दिल्ली के सन्दर्भ में। पिछले 11 वर्षों से सत्ता से बाहर रही कांग्रेस अब एक बार फिर दिल्ली में अपनी खोई हुई जमीन वापस लेने के लिए मैदान में उतर आई है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस ने यह समझ लिया है कि दिल्ली में सिर्फ आम आदमी पार्टी (आप) के खिलाफ खड़ी होकर वह अपनी राजनीतिक वापसी कर सकती है। पार्टी की रणनीति अब पूरी तरह से कांग्रेस के अस्तित्व को फिर से स्थापित करने और दिल्ली की सत्ता में अपनी दावेदारी मजबूत करने पर केंद्रित है।

दिल्ली में कांग्रेस का शासन इतिहास में महत्वपूर्ण रहा है। कांग्रेस ने 1993 से लेकर 2013 तक दिल्ली में अपनी धाक जमा रखी थी। शीला दीक्षित के नेतृत्व में पार्टी ने 15 वर्षों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री के तौर पर राज किया था। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने राजनीति में कदम रखा, कांग्रेस को दिल्ली की सत्ता से बाहर कर दिया। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हो सकी, और आम आदमी पार्टी ने लगातार जीत दर्ज की। हालांकि अब कांग्रेस ने 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार कांग्रेस की योजना केवल सत्ता की वापसी की नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति में अपनी खोई हुई पहचान और जनाधार को वापस पाना है।

कांग्रेस के नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वह अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को किसी भी स्थिति में वॉकओवर नहीं देने वाली। इसके लिए पार्टी ने अपनी ताकतवर रणनीति बनाई है। कांग्रेस ने जहां एक ओर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में अपने दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने की योजना बनाई है, वहीं दूसरी ओर पार्टी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों के खिलाफ खुली जंग छेड़ी है। खासकर कांग्रेस ने केजरीवाल सरकार की नीतियों और उनके प्रभाव को लेकर हमला बोलना शुरू कर दिया है।

कांग्रेस ने दिल्ली में प्रमुख रूप से चुनावी मैदान में उतरने के लिए कुछ बड़े चेहरों को चुना है, जो पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के खिलाफ चुनौती पेश करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को उम्मीदवार बनाया है। संदीप दीक्षित, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं, और उनका नाम खुद में दिल्ली राजनीति का एक बड़ा चेहरा है। शीला दीक्षित दिल्ली से तीन बार विधायक रह चुकी हैं और संदीप दीक्षित भी लोकसभा सांसद रह चुके हैं। संदीप दीक्षित को नई दिल्ली सीट से उतारकर कांग्रेस ने यह स्पष्ट संदेश

दिया है कि वह इस बार केजरीवाल के खिलाफ मजबूत चुनौती पेश करेगी।

कांग्रेस ने न केवल अरविंद केजरीवाल, बल्कि मनीष सिसोदिया जैसे प्रमुख नेताओं के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जंगपुरा सीट से कांग्रेस ने फरहाद सूरी को प्रत्याशी बनाया है, जो इस सीट के तहत आने वाले निजामुद्दान वार्ड से 1996 से पार्षद रहे हैं। सूरी की मुस्लिम और पंजाबी वोटों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसके अलावा, कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव को बादली सीट से मैदान में उतारा है। पटपड़गंज सीट पर कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और विधायक चौधरी अनिल कुमार को अवध ओझा के खिलाफ प्रत्याशी बनाया है। दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन के खिलाफ बल्लिमरान सीट पर कांग्रेस ने हारून युसूफ को उतारा है। सुल्तानपुर माजरा सीट से कांग्रेस ने जय किशन को उम्मीदवार बनाया है, जो दिल्ली में पार्टी के प्रमुख दलित चेहरा माने जाते हैं। मटियामहल सीट पर शोएब इकबाल के बेटे के खिलाफ कांग्रेस ने मो. आसिम को उतारा है, वहीं बाबरपुर सीट पर गोपाल राय के खिलाफ कांग्रेस ने हाजी इशराक को टिकट देकर मुस्लिम वोटों पर जोर दिया है।

कांग्रेस ने अपनी पूरी रणनीति में यह सुनिश्चित किया है कि वह दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार के खिलाफ विपक्ष की सबसे बड़ी ताकत बने। इस मकसद को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने एक श्वेत पत्र भी जारी किया, जिसमें केजरीवाल सरकार की विफलताओं को उजागर किया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि दिल्ली की जनता को केजरीवाल और केंद्र दोनों ने धोखा दिया

कांग्रेस ने न केवल अरविंद केजरीवाल, बल्कि मनीष सिसोदिया जैसे प्रमुख नेताओं के खिलाफ भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। जंगपुरा सीट से कांग्रेस ने फरहाद सूरी को प्रत्याशी बनाया है, जो इस सीट के तहत आने वाले निजामुद्दान वार्ड से 1996 से पार्षद रहे हैं। सूरी की मुस्लिम और पंजाबी वोटों पर मजबूत पकड़ मानी जाती है।

है। पार्टी ने इस श्वेत पत्र में दिल्ली के स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कें, और अन्य आधारभूत संरचनाओं के मामले में सरकार की नाकामी का खुलासा किया। कांग्रेस के नेता अजय माकन ने श्वेत पत्र जारी करते हुए एक कविता भी पढ़ी, जो केजरीवाल सरकार के खिलाफ उनके गुस्से का इजहार थी। माकन ने कविता में कहा, ष्मौका–मौका हर बार धोखा, कोरोना काल में लगा रहा लाशों का अंबार, बस सेंट्रल विस्टा और शीश महल पर बरसा प्यार३ 1780 करोड़ की पेंशन बुजुर्गों की भुलाई, झुग्गियों पर बुलडोजर, 2.80 लाख हुए बेघर...ष इस कविता के जरिए कांग्रेस ने यह दर्शाया कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की जनता के मुद्दों को नजरअंदाज किया है।

कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस में एफआईआर भी दर्ज कराई है। यूथ कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के खिलाफ शिकायत की, जिसमें आरोप लगाया गया कि आम आदमी पार्टी ने अपनी दो प्रमुख योजनाओं, संजीवनी योजना और महिला सम्मान योजना में धोखाधड़ी की है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय लाकरा ने कहा कि जब संबंधित विभाग इन योजनाओं से इनकार कर रहे हैं, तो आम आदमी पार्टी ऐसा कैसे दावा कर सकती है? इसके बाद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तल्खी और भी बढ़ गई है।

अजय माकन ने यह भी कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का समर्थन करना कांग्रेस की सबसे बड़ी भूल थी, जिसकी सजा आज दिल्ली वाले भुगत रहे हैं। माकन ने 2013 में केजरीवाल सरकार के 40 दिन के समर्थन को पार्टी की सबसे बड़ी गलती बताया। उन्होंने कहा कि इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने केजरीवाल के साथ गठबंधन किया था, जो पार्टी के लिए एक भारी गलती साबित हुआ। माकन ने केजरीवाल की आलोचना करते हुए कहा कि वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ मिलकर अपनी सियासी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकते हैं, और उनका कोई स्थिर राजनीतिक विचार नहीं है। माकन ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल ने बीजेपी के साथ कई मामलों में समर्थन किया है, जैसे कि अनुच्छेद 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और सीएए।

बहरहाल, कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत और रणनीति को 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए तैयार किया है। पार्टी के नेताओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस बार वह किसी भी हाल में केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं होने देंगे। कांग्रेस ने सभी रणनीतिक मोर्चों पर अपने कदम बढ़ा दिए हैं और इस बार उसका उद्देश्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि दिल्ली की राजनीति में अपनी खोई हुई पहचान को फिर से स्थापित करना है। पार्टी का पूरा ध्यान अब अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाने और दिल्ली की राजनीति में फिर से सक्रिय रूप से अपनी भूमिका

इसरो की 100वीं सफलता: एनवीएस-02 के जरिये भारत का अपना नैविगेशन सिस्टम नाविक हुआ और मजबूत

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने अपने 100वें लॉन्च मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। एनवीएस–02 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने के बाद इसरो की इस उपलब्धि को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। देशभर की प्रसिद्ध हस्तियों ने इस मिशन की सफलता पर इसरो को बधाई दी है।

इसरो का 100वां मिशन क्या है?

इसरो ने बुधवार सुबह 6:23 बजे अपने 100वें मिशन के तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जीएसएलवी–एफ15 रॉकेट के जरिए 2250 किलोग्राम वजनी नैविगेशन सैटेलाइट एनवीएस–02 को लॉन्च किया। यह उपग्रह नाविक श्रृंखला का दूसरा उपग्रह है। इस श्रृंखला में कुल पांच उपग्रह भेजे जाने हैं। इससे पहले, 29 मई 2023 को जीएसएलवी–एफ12 के जरिए एनवीएस–01, जो दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह था, लॉन्च किया गया था। एनवीएस–02 उपग्रह में एल1, एल5 और एस–बैंड में नेविगेशन पेलोड के साथ–साथ सी–बैंड में रेंजिंग पेलोड भी लगाया गया है, जैसा कि इसकी पहली पीढ़ी के उपग्रह एनवीएस–01 में था।

इस मिशन की खास बातें

- स्वदेशी तकनीक: एनवीएस–02 पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से निर्मित है। बेंगलुरु स्थित यूआर सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी) में डिजाइन और विकसित किया गया है।
- सटीक समय के लिए परमाणु घड़ी: उपग्रह में भारत के सटीक समय की जानकारी देने के लिए एक परमाणु घड़ी (रूबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड) लगाई गई है।
- भारत की स्वायत्तता: यह मिशन भारत को नेविगेशन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्तमान में, देश में जीपीएस और अन्य विदेशी तकनीकों पर निर्भरता को कम करने का प्रयास किया जा रहा है।
- वैश्विक प्रतिस्पर्धा: अमेरिका, रूस, चीन, और यूरोपीय संघ जैसी महाशक्तियों के पास पहले से ही अपने नैविगेशन सिस्टम हैं। भारत अब अपने स्वदेशी नाविक प्रणाली के साथ इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भारत को अपने नेविगेशन सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी?

भारत द्वारा अपना नैविगेशन सिस्टम विकसित करने की सबसे बड़ी वजह रणनीतिक स्वायत्तता और स्वतंत्रता है। 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान, भारत ने अमेरिका से जीपीएस डेटा की मदद मांगी थी, लेकिन अमेरिका ने यह सुविधा देने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बाद भारत को अपनी स्वदेशी नैविगेशन प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई, जिसके बाद 2006 में ष्नाविकष् परियोजना की शुरुआत की गई।

भारत के स्वदेशी नैविगेशन सिस्टम की वर्तमान स्थिति

- 2013 से भारत ने आईआरएनएसएस श्रृंखला की सैटेलाइट्स लॉन्च करनी शुरू कीं। 2013 से 2018 तक कुल 9 उपग्रह भेजे गए।
- इसके बाद, एनवीएस श्रृंखला के उपग्रह लॉन्च किए गए, जो आईआरएनएसएस सिस्टम को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं।
- अब तक कुल 11 सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं, जिनमें से 10 अभी भी कक्षा में हैं और 6 उपग्रह सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं।
- भारत का नैविगेशन सिस्टम किन क्षेत्रों में काम आ रहा है?
- वर्तमान में, यह प्रणाली मुख्य रूप से सैन्य और रणनीतिक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जा रही है।
- एनवीएस उपग्रहों की स्थापना के बाद, नाविक प्रणाली को आम नागरिकों के लिए भी उपलब्ध कराने की योजना है।
- यह प्रणाली 10 मीटर की सटीकता के साथ भारत में और 20 मीटर की सटीकता के साथ पड़ोसी देशों में काम करेगी।
- इसकी कवरेज भारत और उसके आसपास 1500 किलोमीटर तक फैली होगी।

भविष्य में नाविक का वैश्विक विस्तार

इसरो की योजना समय के साथ नाविक को एक वैश्विक नेविगेशन प्रणाली बनाने की है, जिससे यह जीपीएस और ग्लोनास की तरह दुनिया भर में उपयोग किया जा सके। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, पृथ्वी से लगभग 24,000 किलोमीटर ऊपर 24 सैटेलाइट्स का एक अलग समूह स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके लिए इसरो ने केंद्र सरकार को 12 नई सैटेलाइट्स लॉन्च करने का प्रस्ताव दिया है, जिससे धीरे–धीरे नाविक प्रणाली को वैश्विक स्तर पर विस्तारित किया जा सकेगा।

कनाडा की नई सरकार भारत से बनायेगी अच्छे संबंध

अजय कुमार, लखनऊ

कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद हिंदुस्तान में उम्मीद जताई जा रही है कि कनाडा की नई सरकार का भारत के प्रति रूख लचीला होगा। ट्रूडो सरकार जिस तरह से खालिस्तानियों का पक्ष ले रहे थे, उस पर भी लगाम लग सकती है और यदि कनाडा का नया प्रधानमंत्री भारतीय मूल का हुआ तो इसका भी फायदा देश को मिल सकता है। बहरहाल, ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भी कनाडा देशवासियों की समस्या का समाधान नहीं हुआ है। अब सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि आखिर किसे कनाडा का नया प्रधानमंत्री बनाया जाये जो अमेरिका की ट्रंप सरकार के साथ तालमेल रख पाए और भारत जैसे विकासशील देश के भी उससे संबंध अच्छे रहें। भावी प्रधानमंत्री के रूप में कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें दो भारतीय मूल के भी हैं. इन सब में कंजर्वेटिव नेता पियरे पोलीवरे सबसे आगे हैं। पूर्व वित्त मंत्री और उपप्रधानमंत्री हाल ही में कैबिनेट से इस्तीफा देने से पहले ट्रूडो के सबसे मजबूत सहयोगियों में से एक थे. विदेश मामलों की कमान संभालते हुए उन्होंने देश को "अमेरिका और मैक्सिको के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर फिर से बातचीत करने" में मदद की. वह ब्ट्प्क–19 महामारी के लिए कनाडा की वित्तीय प्रतिक्रिया की भी प्रभारी थीं. खबरों के अनुसार जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद भारतीय मूल के दो हिन्दू सांसद चंद्र आये और अनीता आनंद भी प्रधानमंत्री पद के मजबूत दावेदार नजर आ रहे हैं।

अनीता आनंद की पहचान एक विद्वान, वकील और शोधकर्ता की रही है। वह टोरंटो यूनिवर्सिटी में कानून की प्रोफेसर रही हैं जहां उन्होंने इनवेस्ट प्रोटेक्शन और कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जेआर किंबर चेयर का पद संभाला था। वर्तमान में वह कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार में परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री हैं। अनीता आनंद ने क्वीन्स यूनिवर्सिटी से राजनीतिक अध्ययन में बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स), ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से न्यायशास्त्र में बैचलर ऑफ आर्ट्स (ऑनर्स), डलहौजी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ लॉ और टोरंटो यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की है। कनाडा की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अनीता आनंद, पियरे पोलीवरे, क्रिस्टिया फ्रीलैंड और मार्क कार्नी जैसे प्रमुख नामों के साथ नेतृत्व की दौड़ अब तेज हो गई है। भारतीय मूल की अनीता आनंद अपने प्रभावशाली शासन और सार्वजनिक सेवा के अच्छे रिकॉर्ड के कारण सबसे मजबूत दावेदारों में एक माना जा रही हैं। बात कनाडा में भारतीय मूल के सांसद चंद्र आर्य की कि जाये तो प्रधानमंत्री चुनाव के लिए आर्य ने भी ताल ठोक दी है.एक वीडियो क्लीप में आर्य ने कहा कि यदि कनाडा की जनता उन्हें निर्वाचित करती है तो तो वे एक कुशल और छोटी सरकार का नेतृत्व करेंगे, जो देश के पुनर्निर्माण और भविष्य की पीढ़ियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा कनाडाई लोगों के लिए सबसे अच्छा काम

किया है।

हमें ऐसे साहसिक निर्णय लेने होंगे जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी होंगी। चंद्र आर्य ने घोषणा की है कि वह लिबरल पार्टी के नेतृत्व के लिए चुनाव लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कनाडा को संप्रभु गणराज्य बनाने, सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने, नागरिकता आधारित कर प्रणाली लागू करने और फलस्तीन राज्य को मान्यता देने का वादा किया। बात कनाडा की नई सरकार के भारत के साथ सबंध कैसे होंगे इसकी चर्चा हो तो विद्वानों की राय भारत में पक्ष में नजर आ रही है। प्रोफेसर हर्ष वी. पंत का, जो नई दिल्ली स्थित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्ययन और विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष हैं. उन्होंने कहा, कि ट्रूडो ने भारत से निजी कारणों से संबंध बिगाड़े थे, भारत से संबंध सुधारने के लिये जिस तरह की संजीदगी ट्रूडो के इस मुद्दे पर दिखाना चाहिए थी, वो नहीं दिखा रहे थे. उससे दोनों देशों के बीच के संबंधों में काफी नुकसान हुआ।

गौतरलब हो, जस्टिन ट्रूडो पिछले कुछ समय से भारत विरोधी बयानबाजी कर रहे थे. इस बीच, कनाडा ने स्टूडेंट वीजा से जुड़ा एक फैसला लिया था, जिससे भारतीय स्टूडेंट्स की दिक्कतें बढ़ गई थीं. यही वजह है कि भारत और कनाडा के बीच तनाव देखने को मिल रहा है. पंत कहते हैं कुछ समय से मुझे लगता है कि ये बिलकुल स्पष्ट था कि जब तक ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री बने रहेंगे, तब तक भारत–कनाडा के संबंधों में नया मोड़ जिसकी जरूरत है, वो नहीं आ पाएगा।

उधर, वॉशिंगटन डीसी के विल्सन सेंटर थिंक टैंक में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगेलमैन भी भारत और कनाडा के संबंधों को लेकर यही राय रखते हैं. उन्होंने एक्स पर लिखा, कि ट्रूडो का इस्तीफा भारत–कनाडा के बिगड़ते संबंधों को स्थिर करने का मौका दे सकता है।विल्सन ने नई दिल्ली ने द्विपक्षीय संबंधों में गहराई तक फैली समस्याओं के लिए सीधे तौर पर ट्रूडो को जिम्मेदार ठहराया है. हाल के वर्षों में कनाडा एकमात्र पश्चिमी देश है, जिसके भारत के साथ संबंध लगातार खराब हुए हैं।

हिन्दुओं को इग्नोर करने वाले नेताओं को बदलनी होगी अपनी सोच

कई दलों के नेता तो बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर चुप्पी साध रहे हैं, इसके अलावा मुस्लिम संगठन भी बांग्लादेश की हिंसा मुखर नजर नहीं आ रहे हैं, इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन देश के मुस्लिम संगठनों को लानत-मलानत भेज रहे हैं। उन्होंने कहा, ' बांग्लादेश में जिस तरह अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। उन पर जुल्म की सभी सीमाएं पार कर दी गईं।

संजय सक्सेना, लखनऊ

बांग्लादेश में हिंदुओं, बौद्ध सहित अन्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को जलाया व मारा जा रहा है। उनकी संपत्तियां लूटी जा रही हैं। माताओं व बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मंजर ऐसा है कि किसी की भी रूह कांप जाये। बांग्लादेश में जो हो रहा है उसके सामने यूपी के संभल में जो कुछ हुआ कोई मायने नहीं रखता है। हाल में बहराइच में हुई हिंसा भी बांग्लादेश में हिन्दुओं के साथ हो रहे अत्याचार के सामने काफी छोटी नजर आती है। क्योकि संभल हो या बहराइच की हिंसा दोनों ही को विपक्ष कुछ ज्यादा ही बढ़ा-चढ़ाकर हंगामा खड़ा कर रखा है। संभल और बहराइच पर जितना बवाल गांधी परिवार और अखिलेश यादव मचा रहे हैं उतनी ही चुप्पी वह बांग्लादेश में हिन्दुओं और दलितों के साथ हो रहे खून खराबे को लेकर साधे हुए हैं। अखिलेश के पीडीए में पिछड़ा-दलित और अल्पसंख्यकों की बात जरूर की जाती है, लेकिन हकीकत यही है कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक के आगे किसी को तरजीह नहीं देते हैं। अखिलेश दलितों और पिछड़ों की बात सिर्फ इस वर्ग के वोटरों को गुमराह करने के लिये करते हैं। इसी तरह से दलितों और पिछड़ों को इंसाफ दिलाने के लिये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनकी टीम जातिगत जनगणना कराये जाने के लिये हाय-तौबा तो करती है, लेकिन उनका भी इससे कोई लेनादेना नहीं है। उनको भी सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक नजर आता है।

दरअसल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही मुस्लिम वोट बैंक पर कब्जेदारी के चक्कर में एक-दूसरे के साथ-साथ (इंडिया गठबंधन में शामिल दोनों दल) होते हुए भी सियासी

दुश्मन बनते जा रहे हैं। मुस्लिम वोट बैंक की खातिर यूपी में राहुल गांधी सपा प्रमुख की कंधे पर चढ़कर उनकी पीठ में 'छूरा' भोंकने की कोशिश कर रहे हैं तो अखिलेश यादव जिन्होंने भी नेताजी मुलायम सिंह के बाद मुस्लिम वोटरों को

अपने जाल में फांस रखा है वह मुस्लिम वोटरों पर अपनी पकड़ कतई ढीली करने को तैयार नहीं है। इसी के चलते यूपी में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की राह जुदा होती जा रही है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव की बात हो या फिर हाल में सम्पन्न नौ विधान सभा सीटों की, दोनों ही बार अखिलेश ने कांग्रेस के साथ होते हुए भी उससे दूरी बनाये रखी। लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश ने गठबंधन का धर्म निभाते हुए कुछ सीटें कांग्रेस के लिये छोड़ भी दी थीं, लेकिन उप चुनाव में तो कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दी। आलम यह है कि जब संभल में हुई हिंसा के बाद राहुल गांधी ने वहां जाने का कार्यक्रम बनाया तो समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश के चचा रामगोपाल यादव इसे राहुल की नौटंकी करार दे दिया। इसको लेकर कांग्रेस और सपा के नेताओं के बीच एक–दूसरे के खिलाफ खूब बयानबाजी हुई, लेकिन रामगोपाल यादव की बात सच थी। इस बात का अहसास जल्द हो भी गया। ऐसा इसलिये था क्योंकि राहुल गांधी और उनकी नई–नई सांसद बहन प्रियंका वाड्रा को जब लोकसभा में संभल के पीड़ितों की आवाज उठाने का मौका मिला तो इन दोनों (राहुल–प्रियंका) के साथ–साथ पूरी कांग्रेस अडानी–अडानी करती रह गई। कांग्रेस के इन दिग्गज नेताओं ने एक भी शब्द संभल हिंसा को लेकर नहीं बोला।

बांग्लादेश में हिन्दुओं और खासकर दलितों के खून खराबे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की चुप्पी न तो बीजेपी को रास आई न ही बसपा सुप्रीमो मायावती को यह बर्दाश्त हुआ। योगी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे कुछ ज्यादा ही दुखी हैं। वह राहुल और अखिलेश जैसे नेताओं का नाम लिये बिना सवाल करते हैं "आज कुछ लोग समाज को धोखा दे रहे हैं। वे ही लोग समाज में झूठ फैला रहे हैं। हैदराबाद के निजाम और उनके रजाकारों की ओर से जब दलितों के गांव जलाए जा रहे थे तब भी वे चुप थें उस दौरान उनका शोषण हो रहा था। तब भी बाबा अंबेडकर ने खुला पत्र लिखा था कि

बांग्लादेश में हिन्दुओं और खासकर दलितों के खून खराबे को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं की चुप्पी न तो बीजेपी को रास आई न ही बसपा सुप्रीमो मायावती को यह बर्दाश्त हुआ। योगी बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उससे कुछ ज्यादा ही दुखी हैं। वह राहुल और अखिलेश जैसे नेताओं का नाम लिये बिना सवाल करते हैं आज कुछ लोग समाज को धोखा दे रहे हैं। वे ही लोग समाज में झूठ फैला रहे हैं।

निजाम की रियासत के सभी दलित रियासत को छोड़कर महाराष्ट्र चले जाएं, लेकिन अपना धर्म और मत न बदलें। पड़ोसी मुल्कों में अल्पसंख्यक हिंदुओं की घटती आबादी पर सीएम योगी ने कहा कि साल 1947 में पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं की बड़ी तादाद में आबादी रहती थी। बांग्लादेश में साल 1971 तक 22 फीसदी हिंदू रहा करते थे, लेकिन आज उनकी संख्या 6 से 8 फीसदी ही रह गई है। योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कहा, "जो लोग हमेशा दलितों को अपना वोट बैंक बना कर उनका शोषण करते आए हैं, वे आज बांग्लादेश की घटना पर मौन हैं. उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा। वे सच को स्वीकार नहीं कर सकते और न ही सच बोल सकते हैं। सिर्फ संविधान की प्रति दिखाकर ढोंग कर रहे हैं। उन्हें बाबा साहेब के मूल्यों से कोई लेना–देना ही नहीं है।

ऐसे ही आरोप बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगा रही हैं। उन्होंने बांग्लादेश में हिन्दुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं को लेकर विपक्षी दलों को घेरा और पूछा कि मुख्य विपक्ष दल होने के बाद भी कांग्रेस और सपा इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? ये दोनों दल सिर्फ मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए सिर्फ संभल हिंसा की बात कर मुस्लिम समाज को लड़वा रही हैं। मायावती ने मांग की कि केंद्र सरकार को बांग्लादेश के दलितों को भारत लाना चाहिए। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि संसद चल रही है और विपक्षी दल देश और यहां के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी हुई हैं। इन्हें बाकी मुद्दों से कोई लेना–देना नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये दल मुस्लिम समाज को भी तुर्क और नॉन तुर्क को आपस में लड़ा रही है, जिससे मुस्लिम समाज को भी सतर्क रहना है।

कई दलों के नेता तो बांग्लादेश में हो रही हिंसा को लेकर चुप्पी साध रहे हैं, इसके अलावा मुस्लिम संगठन भी बांग्लादेश की हिंसा मुखर नजर नहीं आ रहे हैं, इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी नेता शाहनवाज हुसैन देश के मुस्लिम संगठनों को लानत–मलानत भेज रहे हैं। उन्होंने कहा, ' बांग्लादेश में जिस तरह अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। उन पर जुल्म की सभी सीमाएं पार कर दी गईं। उस पर भारत सरकार की पूरी नजर है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, धार्मिक स्थल जलाए जा रहे हैं, धर्म गुरुओं को मारा–पीटा जा रहा है, उस पर मुस्लिम संगठनों के लोग चुप हैं। शाहनवाज ने कहा, अगर फिलिस्तीन या ईरान में मुस्लिमों के साथ कुछ होता है, तो ये लोग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वे मारे–काटे जा रहे हैं, लेकिन उलेमाओं की जुबान खुल ही नहीं रही है। वह कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। पूरी दुनिया में अल्पसंख्यकों को कैसे रखा जाता है, उसके लिए आदर्श देश भारत है। अल्पसंख्यकों के लिए भारत से अच्छा कोई देश नहीं हो सकता। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की क्या हालत कर दी गई। पूरे मुस्लिम समुदाय को खुलकर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर मार्च निकालना

बीजेपी के खिलाफ 2027 में फिर बदलेगा सियासी समीकरण

उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर से सियासी समीकरण काफी तेजी के साथ बदल रहा हैं। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की विरोध की हांडी नहीं पक पाने के कारण प्रदेश में एक बार फिर से नए सियासी समीकरण उभरते नजर आ रहे हैं।

अजय कुमार, लखनऊ

इस नये समीकरण में तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी का अहम रोल हो सकता है। इसी वजह से समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की कमान ममता बनर्जी को दिये जाने की मांग का भी समर्थन कर रहे हैं। हो सकता है 2027 के विधानसभा चुनाव के समय तक समाजवादी पार्टी कांग्रेसी पंजे से अपना हाथ छुड़ाकर ममता बनर्जी के कहने पर एक बार फिर से मायावती के साथ बुआ भतीजे वाला रिश्ता निभाते नजर आए। ऐसा होता है तो यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है। यह संभावना है इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों या महीनों से कांग्रेस समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश कर रही है। सपा–कांग्रेस के बीच दूरियां लगातार बढ़ने के साथ एक–दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक मंचों से बयानबाजी भी हो रही है। महाराष्ट और हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की नाकामी भी इसमें एक अहम कड़ी समझा जा रहा है। यही दूरियां ही हैं कि संसद के अंदर भी सपा–कांग्रेस विभिन्न मुद्दों पर मजबूती से एक साथ नहीं दिख रहे हैं। सपा नेताओं का कहना है कि संभल मामले में उसके सांसद पर मुकदमे दर्ज किए जाने का कांग्रेस ने उस तरह विरोध नहीं किया जैसी उससे अपेक्षा थी। बताते हैं कि लोकसभा में फैजाबाद (अयोध्या) के सपा सांसद अवधेश प्रसाद की सीट

पीछे होने पर भी दोनों दलों के रिश्तों में दरार आई है। सपा का मानना है कि सीटिंग प्लान पर बात के समय कांग्रेस ने उसे भरोसे में नहीं लिया। वहीं, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सदन में अदाणी मामले में उसे सपा का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। हाल यह है कि जेल में बंद सपा के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान ने भी इंडिया ब्लॉक को जेल से एक संदेश भेजा है। इसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया ब्लॉक को मुसलमानों पर हो रहे हमलों पर अपनी नीति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी को भी लिखा कि संभल की घटना के जैसे ही रामपुर में हुए अत्याचार का मुद्दा भी संसद में उतनी ही मजबूती से उठाना चाहिए।

कांग्रेस और सपा के बीच दूरियां तब और बढ़ गईं जब सपा कि तरफ से कहा जाने लगा कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस की जगह तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी को दिए जाने पर सपा को एतराज नहीं है।

बता दें लोकसभा चुनाव के बाद कई चुनावों में कांग्रेस की लगातार हार के बाद इंडिया गठबंधन में अंतर्विरोध बढ़ रहे हैं। उधर दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि यूपी की राजनीति एक बार फिर पलट सकती है। सपा और कांग्रेस के बीच आई दूरियों के बीच मायावती का रुख नई राजनीतिक समीकरणों को जन्म दे सकता है। बहराल, सपा नेताओं का कहना है कि संभल मामले में उसके सांसद पर मुकदमे दर्ज किए जाने का कांग्रेस ने उस तरह विरोध नहीं किया जैसी उससे अपेक्षा थी। बताते हैं कि लोकसभा में फैजाबाद (अयोध्या) के सपा सांसद अवधेश प्रसाद की सीट पीछे होने पर भी दोनों दलों के रिश्तों में असहजता पैदा हुई है। सपा का मानना है कि सीटिंग प्लान पर बात के समय कांग्रेस ने उसे भरोसे में नहीं लिया। वहीं, कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि सदन में अदाणी मामले में उसे सपा का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है।

रिश्तों में खटास का ही नतीजा है कि सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने कहा कि ममता बनर्जी वरिष्ठ नेता हैं। पार्टी हाईकमान भी यही चाहता है कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करें। सपा के प्रमुख महासचिव प्रो. रामगोपाल भी कह चुके हैं कि वे राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का नेता नहीं मानते हैं। इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति में शामिल सपा के एक नेता बताते हैं कि कांग्रेस गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं है। उसके नेता चुनाव के वक्त ही सक्रिय होते हैं जिससे जनाधार नहीं बढ़ता। ऐसे में बेहतर होगा कि गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी करें। भाजपा को मात देने के लिए रणनीति के साथ जनता के बीच लगातार जुटे रहने की जरूरत है।

बात बीएसपी की की जाए तो हरियाणा व महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव और यूपी के उपचुनाव में कांग्रेस व सपा के बीच बढ़ी दूरियों का सियासी लाभ बसपा को मिलने की उम्मीद है। पार्टी तेजी से बदले राजनीतिक घटना पर नजर बनाए हुए है। यदि कांग्रेस और सपा के बीच बात नहीं बनी तो इसकी वजह से बनने वाले तीसरे मोर्चा का बसपा अंग बन सकती है। जानकारों की मानें तो वर्तमान में पार्टी को अपना वजूद बचाने और देश की राजनीति में अपनी प्रासंगिकता को बरकरार रखने के लिए इसकी जरूरत भी है। बसपा के इतिहास पर नजर डालें तो वर्ष 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसे बहुमत मिला था। इससे पहले बसपा दूसरे दलों की मदद से सरकार बनाती रही, जिसका लाभ उसे लोकसभा चुनावों में भी मिलता गया। वर्ष 2012 में बसपा ने फिर अकेले दम पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया, जो गलत साबित हुआ। यही हाल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हुआ। 2019 में बसपा ने सपा के साथ गठजोड़ कर लोकसभा चुनाव लड़ा और 10 सांसदों वाली पार्टी बनी। हालांकि इसके बाद वर्ष 2022 का विधानसभा चुनाव और 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने से उसे भारी नुकसान का सामना करना पड़ गया।

अब पार्टी की उम्मीदें तीसरा मोर्चा बनने पर टिकी हैं। वैसे तो मायावती सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों दलों को एक मंच पर ला सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की मानें तो कांग्रेस को दरकिनार कर अगर तीसरा मोर्चा बना तो ममता बनर्जी उसकी निर्विवाद नेता बन सकती हैं। पहले उन्हें मायावती से चुनौती मिलने के जो समीकरण बने थे, वो बीते चुनावों में बसपा के लगातार घटते जनाधार की वजह से ध्वस्त हो चुके हैं। अब बसपा को अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने के लिए दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ सकता है।इसके साथ ही बसपा सुप्रीमो ने पुराने

ट्रंप खाली करायेंगे गाजा पट्टी

मिस्र और जॉर्डन से फलस्तीनियों को शरण देने की अपील की

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह मिस्र और जॉर्डन के नेताओं से आग्रह करेंगे कि वे गाजा के लोगों को अपने देश में शरण दें, ताकि गाजा में स्थिति को दोबारा सुधारने का प्रयास किया जा सके। उन्होंने कहा कि गाजा के निवासियों का पुनर्वास अस्थायी या दीर्घकालिक हो सकता है।

20 जनवरी को अमेरिका में नई सरकार ने कार्यभार संभाल लिया है। चार साल के अंतराल के बाद डोनाल्ड ट्रंप फिर से सत्ता में लौट आए हैं। सत्ता में वापसी के बाद ट्रंप आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। हाल ही में उन्होंने कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों पर टैक्स लगाने की बात कही है और ब्रिक्स देशों पर भी निशाना साधा है। इस्राइल और हमास के बीच संघर्षविराम के दौरान ट्रंप के बयान ने सबका ध्यान खींचा है।

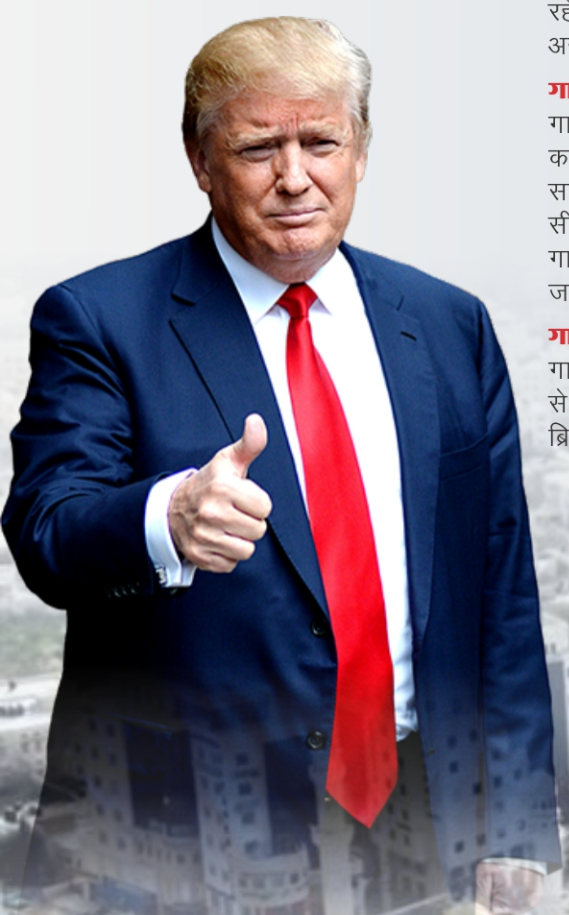

उन्होंने गाजा पट्टी को खाली कराने का सुझाव दिया और साथ ही मिस्र और जॉर्डन से गाजा के निवासियों को शरण देने की अपील की। ट्रंप का कहना है कि इस्राइल के लंबे सैन्य अभियानों के कारण गाजा अब पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। उन्होंने कहा कि वह कुछ अरब देशों के साथ मिलकर एक नई जगह पर आवास बनाने की योजना पर विचार कर रहे हैं, जहां लोग शांति से बदलाव का अनुभव कर सकें।

गाजा पट्टी क्या है?

गाजा पट्टी लगभग 365 वर्ग किलोमीटर का छोटा क्षेत्र है। इसके एक ओर भूमध्य सागर है और बाकी तीन ओर इसकी सीमाएं इस्राइल और मिस्र से लगती हैं। गाजा पट्टी फलस्तीनी क्षेत्रों में से एक है, जबकि दूसरा क्षेत्र वेस्ट बैंक है।

गाजा पट्टी का नियंत्रण और इतिहास

गाजा का इतिहास लंबे समय से विवादों से भरा रहा है। 1918 से 1948 तक ब्रिटेन के नियंत्रण में रहने के बाद 1948 में मिस्र ने इस पर कब्जा कर लिया। 1967 के छह दिन के युद्ध में इस्राइल ने गाजा और वेस्ट बैंक पर कब्जा कर लिया। 1993 के ओस्लो समझौते के बाद गाजा पर फलस्तीन का सरकारी नियंत्रण हुआ। 2005 में इस्राइल ने गाजा से अपने सैनिक और बस्तियां हटा लीं, लेकिन 2007 से इस्राइल ने गाजा पर जमीन, वायु और समुद्री नाकाबंदी कर रखी है।

गाजा में आज कौन नियंत्रण में है?

हमास, जो 2006 के चुनावों के बाद गाजा की सत्ता में आया, अब इस क्षेत्र पर शासन करता है। यह संगठन इस्राइल के साथ संघर्ष में सबसे सक्रिय भूमिका निभाता है। इस्राइल की नाकाबंदी ने गाजा के विकास को रोक दिया है।

गाजा पट्टी की जनसंख्या

गाजा पट्टी, जिसकी लंबाई 41 किलोमीटर और अधिकतम चौड़ाई 12 किलोमीटर है, में लगभग 23 लाख लोग रहते हैं। यह क्षेत्र दुनिया के सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले इलाकों में से एक है। यहां बेरोजगारी दर सबसे अधिक है, और अधिकांश लोग बुनियादी जरूरतों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता पर निर्भर हैं।

मेरा पन्ना

कवयित्री प्रज्ञा श्रीवास्तव प्रज्ञाञ्जलि

सच कहूँ...

हर बार मिलती है सजा
बेगुनाह होने पर भी
कभी सहने की
तो कभी कहने की
पर सजा मिलना तो तय रहता है
हर दूसरी कहानी में
मिलती है सजा उसको
हँसने की, रोने की, मुस्कुराने की
जन्म से लेकर मौत तक
कदम-कदम पर मिलती है सजा
सच कहूं
सजा पाकर भी जीती है जिंदगी
पल भर का प्यार पाकर
भूल जाती है
और फिर से जी उठती है
ताकत तो होती है
सहने की ताकत
खुश होती है वो
खिलखिलाती है
अचानक
न जाने क्यों
एक गुबार उठता है
बेवजह ही
फिर मिल जाती है सजा
हर बार की तरह
छिपकर रातभर
भिगोती है तकिया
और सुबह उठकर
लग जाती है काम में
हारती नही वो
लड़ती है
कमजोर तो बिल्कुल नही होती
बेवजह सजा पाकर
केवल एक औरत ही जी सकती है

RNI No. UTTHIN/2021/80704

प्रकाशन की तिथि- प्रत्येक माह की 7 तारीख
प्रेषण दिनांक- प्रत्येक माह की 10 तारीख

विभिन्न विषयों पर आधारित हिन्दी मासिक पत्रिका

तीर निशाने पर

विशिखा

राजस्थान की राजधानी जयपुर एवं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाद विशिखा

अब शीघ्र ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से भी प्रकाशित...

तीर निशाने पर विशिखा

मुख्यालय : विशिखा मीडिया 191/56, सेक्टर-19, प्रताप नगर, सांगानेर
जयपुर-302033 (राज.)
Contactus:+911413562171, 9587455444
E-mail:vishikhamedia@gmail.com | Website:www.vishikhamedia.in
vishikhamedia/ _vishikhamedia/ vishikhamedia